असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत

सरकारी प्रतिवेदन

09 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा | बुधवार, तिथि 09 मार्च, 2016 ई0

द्वितीय सत्र | 19 फाल्गुन, 1937 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, राज्य सरकार के मंत्री, अब्दुल गफूर और वहां के स्थानीय विधायक महोदय सीवान जेल में जाकर वहां पर पूर्व बाहुबली जो सांसद महोदय हैं, जिन पर हत्या का आरोप है, रंगदारी का महोदय आरोप है ऐसे लोगों से मिलकर के जेल मैनुअल का महोदय धज्जी उड़ाया जा रहा है महोदय । नीतीश कुमार जी के कानून का राज का मतलब जिस तरह से धज्जी महोदय बिहार में उड़ाया जा रहा है । महोदय, राज्य सरकार के मंत्री महोदय जिस तरह से जेल मैनुअल का उल्लघंन करके जेल में जाकर दरबार लगाने का काम कर रहे हैं इससे साबित महोदय होता है कि बिहार में अपराधी सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त करने का काम करते हैं और इस तरह से पूरे में अराजकता का माहौल है महोदय ।

अल्पसूचित प्रश्न

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 (श्री संजय सरावगी)

श्री विजय प्रकाश: महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में बाल श्रम की बहुतायत वाले जिलों में बाल मजदूरों का सर्वेक्षण हुआ है । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पोषित एवं संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCPL) के अंतर्गत आच्छादित राज्य के 24 जिलों में समय समय पर केन्द्र सरकार के निदेश के आलोक में एवं केन्द्र सरकार द्वारा ही उपलब्ध करायी गयी राशि से संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति द्वारा सर्वेक्षण कार्य कराया जाता है।

2. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग ने NCPL के अंतर्गत संचालित होने वाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान पर विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए सभी जिलां में पूर्णकालिक आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया है । उक्त प्रस्ताव के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध विभाग के स्तर से भी भारत सरकार से पत्रांक-749, दिनांक 26.02.16 द्वारा किया गया है।

3. बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु सभी जिलों में आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में उत्तर सं0-(01) एवं (02) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर भाजपा के मा0 सदस्यगण सदन के वेल में आ गए)

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, मांग करते हैं कि सरकार राज्य के मंत्री से इस्तीफा ले और जहां दरबार लगाया गया है इसकी जांच करने की मांग राज्य सरकार से करते हैं महोदय । बहुत गंभीर मामला महोदय है । सत्ताधारी दल के मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय जिस तरह से जेल में जाकर वैसे व्यक्ति से जिन पर हत्या का सजायाफ्ता, अपहरण, बलात्कार का केस है महोदय, सैकड़ों मुकदमें चल रहे हैं वैसे बाहुबली पूर्व सांसद से जेल में जाकर मिलने जाते हैं, दरबार लगाने जाते हैं । बिहार में कानून का राज का महोदय धज्जी उड़ाया जा रहा है । बिहार में अपराधियों का महोदय सरकार का संरक्षण प्राप्त है । मांग करते हैं महोदय ऐसे मंत्री से इस्तिफे की मांग करते हैं और इन सारे मामले की जांच कराने की भी मांग करते है महोदय ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, हमलोगों की बातें सुन लिया जाय, सुन लिया जाय । महोदय, हमलोगों ने मांग किया है और हमलोगों ने आग्रह आपसे किया कि सरकार इस बात का खुलासा करे इन सारी बातों की जांच की घोषणा करे महोदय और वैसे मंत्री को इस्तिफा देने की हम मांग करते हैं महोदय । यदि सरकार इस्तीफा नहीं लेती है तो बरखास्तगी का हमलोग मांग करते हैं महोदय ।

अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष आप पहले एक चीज तो समझ लें कि आपके सदस्य जगह पर जायेंगे तब न आप बोलेंगे ।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, हम बोल चुके । महोदय बोल चुके और सारी बातों को रख चुके । हमने आग्रह महोदय आपसे किया है हमने सारी बातों को महोदय रख दिया है महोदय आपके सामने, सदन के सामने रख दिया है महोदय रख दिया है सरकार से जवाब चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं ऐसे मंत्री का अविलंब इस्तीफा लिया जाय और सारे मामले की महोदय जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष: आप अपने सदस्यों को जगह पर तो बैठाइये ।

श्री प्रेम कुमार: काफी नाराजगी महोदय है । पूरे राज्य में महोदय कानून का राज का हवा महोदय निकल गया है । कानून के राज का इनके मंत्री धज्जी उड़ाने का काम कर रहे हैं । पूरे बिहार में महोदय सत्ताधारी लोगों का अपराधियों का महोदय संरक्षण प्राप्त करते हैं और पूरे बिहार में संदेश महोदय गया है। पूरे बिहार में भय का वातावरण फिर से बनने लगा है । सरकार कुछ कर नहीं रही है महोदय । राजवल्लभ यादव को सरकार पकड़ नहीं रही है । एक महीने हो गए और बलात्कारी का आरोपी राजवल्लभ यादव को पकड़ने में सरकार पूरी तरह विफल रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप बोल रहे हैं और ये नारा भी लगा रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार: चलेगा महोदय, नारा भी चलेगा और भाषण भी चलेगा ।

अध्यक्ष: यह अच्छा तरीका नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार: इतनी बड़ी घटना घटी है महोदय । आपसे आग्रह है महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय । सरकार को निदेश दें महोदय कि सरकार वैसे मंत्री से इस्तीफा ले महोदय जिन्होंने जेल मैनुअल का धज्जी उड़ाकर जेल में दरबार लगाने का काम किया है। जिस पर महोदय सैकड़ों बलात्कार, हत्या और अपराधी घटनाओं में अपहरण के मामले में शहाबुद्दीन सजायाफ्ता महोदय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इनलोगों को जगह पर तो बैठाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–252 (श्रीमती भागीरथी देवी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–260 (श्री राजेश कुमार)

श्री शैलेश कुमार: महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 5 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है तथा डाउन स्ट्रीम में 3 कि0मी0 की दूरी पर पुल प्रस्तावित है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क निर्मित है ।

इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, सारा कार्य स्थगित करके सरकार से जवाब दिलवाइये महोदय । महोदय गंभीर मामला है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–712 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या–713 (श्री (मो0) तौसीफ आलम)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री शैलेश कुमार: महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. जांच हेतु लिखा गया है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन (मुख्यालय), ग्रामीण कार्य विभाग को लिखा गया है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री (मो0 तौसिफ आलम): अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनायी नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय हम जांच की मांग करते हैं और सरकार से चाहेंगे कि किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा इसमें जांच किया जाय ताकि प्राक्कलन में जो गड़बड़ी हुई है सही न्याय मिल जाय ।

श्री शैलेश कुमार: हम जांच गुणवत्ता प्रबंधन ग्रामीण कार्य विभाग को लिखा हुए हैं उसमें मा0 सदस्य स्वयं उपस्थित रहें ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्य-714 (श्री मदन मोहन तिवारी)</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री शैलेश कुमार: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पथ की लंबाई 5.5 कि0मी0 है । पथ श्रेणी-I में सम्मिलित नहीं है । वर्तमान में राज्य अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-1 में सम्मिलित पथों का अनुरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का मरम्मति कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

(व्यवधान)

श्री मदन मोहन तिवारी: दस साल से वह रोड जर्जर है सरकार का ध्यान नहीं है कब तक बन जाएगा मंत्री जी।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री शैलेश कुमार: महोदय, हमने माननीय सदस्य को कहा कि श्रेणी–2 में इसको हम ले लिये हैं श्रेणी–1 का काम जैसे समाप्त होगा श्रेणी–2 में हम इसे ले लेंगे ।

टर्न–2/बिपिन/09.3.2016

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 715(श्री सदानन्द सिंह)</u>

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दो पथ की स्थिति निम्नवत् है :–

1.भागलपुर जिला के गौराडीह प्रखंड अंतर्गत एल.033 पी.डब्लू.डी. पथ नं. –12 संतनगर पथ निर्माण कार्य– यह पथ प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा इसकी लम्बाई 0.700कि.मी. है एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि–03.02.2016 है। इस पथ में मिट्टी कार्य, पुलिया निर्माण कार्य, जी.एसी.बी. कार्य एवं डब्लू.बी.एम. ग्रेड–2 कार्य पूर्ण होने के साथ 400मीटर लम्बाई भाग में डब्लू.बी.एम. ग्रेड–3 का कार्य भी पूर्ण हो चुका है । कालीकरण कार्य हेतु बिटुमेन का भी क्रय कर लिया गया है । संवेदक द्वारा संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है जिसके अनुसार एक माह के अन्दर शेष कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा ।

2. एल. 039 पी.डब्लू.डी. पथ नं.-12 से मंगलाचक पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथ निर्माण कार्य- यह पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा इसकी लम्बाई 1 कि.मी. है । एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 03.02.2016 है । इस पथ में 0.35 कि0मी0 में पी.सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। संवेदक द्वारा संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है जिसके अनुसार एक माह के अंदर शेष कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : एक महीना में करा देंगे ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 716(श्री राम नारायण मंडल)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, संरक्षण दीजिए ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 717(डॉ0 रामानंद यादव)</u>

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2.वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 2.00 कि.मी. की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम में 3.00 कि.मी. की दूरी पर पुल निर्मित है ।

प्रश्नाधीन पुल स्थल पर पुल निर्माण विचाराधीन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, क्वेश्चन आवर रोककर सरकार का जवाब करवाइए महोदय । इस्तीफा दिलवाइए महोदय ।

(व्यवधान)

डा0 रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय, नारायण टोला पुल नहीं बनने के कारण वहां के ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं के वलवा हाई स्कूल में आवागमन में कठिनाई होती है । बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाता है तो छात्र-छात्रा एवं ग्रामीणों को कठिनाई हो जाती है । ऐसी परिस्थिति में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक समय-सीमा तय करके आगामी वित्तीय वर्ष में पुल का निर्माण कराना चाहते हैं या नहीं ?

श्री शैलेश कुमार: संसाधन उपलब्धता के बाद इसको देख लेंगे महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0: 718(डॉ0 शकील अहमद खाँ)

(व्यवधान)

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन अंश प्रथम, कुर्सेल पंचायत के शिशिया ग्राम में रीघा नदी पर छतियन घाट के पास 90 मीटर की चौड़ी नदी है। यह ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चौकी से कचौरा पथ में अवस्थित है । इस पथ में पी.एम.जी.एस.वाई. (आर.आर.पी.-II) योजनान्तर्गत कुल चार पुल स्वीकृत है । इनमें से एक पुल का निविदा होकर कार्य आवंटित हो चुका है तथा शेष तीन पुलों का पुन:निविदा होकर निविदा निस्तार की प्रक्रिया में है । इसी तीन पुल में प्रश्नाधीन पुल शिशिया (डुमरिया) के पास छतियन घाट पर स्वीकृत है । इसकी निविदा निस्तार की कार्रवाई की जा रही है, तत्पश्चात् पुल का निर्माण कराया जाना सभ्भव हो सकेगा ।

प्रश्नाधीन दूसरा अंश, कुर्सेल गांव से रेलवे गुमटी जाने वाली सड़क जिसकी लंबाई 1 कि.मी. है, कच्चा पथ है । कुर्सेल गांव पथ निर्माण विभाग के पथ पर है । इसलिए यह पथ न्यूनतम अहर्ताओं को पूरा नहीं करने के कारण राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । इस पथ पर हुए कटाव पर पुल बनाया जाना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नाधीन तृतीय अंश कचौरा गांव के महानंदा बांध पर जाने के लिए 20मीटर का कटाव है । महानंदा बांध गांव के किनारे से गुजरती है । बांध के उस पार कोई बसावट नहीं है । प्रश्नाधीन पुल गांव के पिछले भाग में है तथा सिर्फ गांव से महानंदा बांध पर जाने

के लिए है । कचौरा गांव पूर्ण से निर्मित पथ चौकी से कचोर (पी.एम.जी.एस.वाई.) योजनान्तर्गत निर्मित पथ से जुड़ा हुआ है । प्रश्नाधीन कटाव के अपस्ट्रीम में 250मीटर की दूरी पर एक उच्च स्तरीय पुल है, जो पथ निर्माण विभाग के पथ पर है। चूँकि यह कटाव ग्रामीण कार्य विभाग के पथ के आरेखन पर नहीं है, यहां पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

डा0 शकील अहमद खॉं: धन्यवाद ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, महोदय ...

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0: 719(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0: 720(श्री जनार्दन मांझी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, 1. बाइपास निर्माण एक नई योजना होगी । किसी भी नये पथ का निर्माण उनके संगत पहलुओं यथा वर्त्तमान ट्रैफिक डेंसिटी, जमीन की उपलब्धता, निधि की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

उक्त पहलुओं का अध्ययन कर बाईपास निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार किया जाना आवश्यक है । वर्त्तमान में इस बाईपास का निर्माण कार्य-योजना में सम्मिलित नहीं है ।

तारांकित प्रश्न सं0: 721(श्री मुजाहिद आलम)

(व्यवधान)

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के डाउन स्ट्रीम में 365 मीटर की दूरी पर 216.5 मीटर आकार का पुल निर्माणाधीन है । प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मुजाहिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुल है कटहलबाड़ी, कैरीबीरपुर पंचायत में है, एक हजार की आबादी प्रभावित हो रही है । इसलिए इसको कोर नेटवर्क में जोड़ते हुए पुल बनाने की आवश्यकता है । इससे बहुत बड़ी आबादी बरसात के दिन में मुख्य सड़क तक बीमारी आदि में हॉस्पिटल जाने में कठिनाई होती है इसलिए इस पुल का निर्माण अति आवश्यक है । माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र इस पुल को स्वीकृत करने की कृपा की जाए ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: क्वेश्चन का क्या महत्व है महोदय। बिहार में कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0: 722(श्री अमरनाथ गामी)

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पर साल में 11 महीने तक आवागमन चालू रहता है । अत्यधिक बाढ़ आने पर ही रास्ता बंद होता है । उक्त स्थल पर पहले से ही 12 भेंट का कॉजवे बना हुआ है ।

अत: वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अमरनाथ गामी : महोदय, यह दो जिला को जोड़ने वाला पथ है । अतिमहत्वपूर्ण है । आवागमन अधिक है और जवाब सुनाई नहीं दिया है । हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से मंत्री महोदय उक्त आवश्यकता को देखते हुए कब तक इस काम को पूरा करवा देंगे?

अध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं पुल जिला को जोड़ता है, इसको अगले वित्तीय वर्ष में देखवा लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: पूरा राज्य महोदय, असुरक्षित हो गया है । पूरे राज्य में आपराधिक घटनाएं हो रही है । सत्ताधारी दल के मंत्री अपराधियों से हाथ मिलाने जाते हैं ...

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0: 723(डॉ0 रंजु गीता)</u>

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सड़वारा से रसलपुर भाया गाछी टोल सुपलगरहा का निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है । सुपलगरहा से निमाही मुशहरी टोल पथ की लम्बाई 2.0 कि. मी. है जिसका निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया गया है । पथ का पॉच वर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुका है । राज्य अनुरक्षण नीति के तहत पथ के अनुरक्षण हेतु श्रेणी-2 में सम्मिलित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।(व्यवधान)

टर्नः–3/राजेश/9.3.16

तारांकित प्रश्न संख्या– 724 (श्री सदानन्द सिंह)

श्री शैलेश कुमारः– महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा इसकी लम्बाई 2489 कि0मी0 है। इस पथ में मिट्टी कार्य, पुलिया निर्माण कार्य एवं डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–3 तक कार्य पूर्ण हो चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 12.4.16 है। इसे निर्धारित समय सीमा तक पूर्ण करा लिया गया है।

श्री सदानन्द सिंहः– महोदय, सिर्फ एक जानकारी दे दें माननीय मंत्री जी कि कब तक पथों को पूर्ण करा देंगे। (व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या– 725 (श्री दिनकर राम)

(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या– 726 (श्री रवि ज्योति कुमार)

श्री शैलेश कुमारः– महोदय, 1:– उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

2:– वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है, जिसपर वर्तमान में ईट सोलिंग किया हुआ है। यह पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–4 पर अंकित है, जिसका डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रस्तावित किया जा रहा है।

भारत सरकार से स्वीकृत्योपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री रवि ज्योति कुमार:- इस हल्ला में कुछ सुनाई नहीं पड़ा, हम क्या पूछें। सर, कब तक बनायेंगे।

अध्यक्ष:- कब तक बनायेंगे।

श्री शैलेश कुमार:- महोदय, डी0पी0आर0 भारत सरकार को प्रस्तावित है। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक-4 पर अंकित है। वहॉ से स्वीकृत्योपरांत ही हम आगे की कार्रवाई कर सकेंगे महोदय।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, सरकार से इसपर जवाब दिलवाइये। सरकार की मंशा क्या है,यह हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, ऐसे मंत्री जिन्होंने जेल मैनुएल कानून को हाथ में लेने का काम किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब इसपर चाहिए, सरकार बताये ..... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार:- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जिस ढंग से हर दिन प्रश्नकाल को एवं ध्यानाकर्षण को बाधित करते हैं, सदन में अव्यवस्था फैलाते है, जबकि बिहार विधान सभा का कार्य संचालन नियमावली है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विषय को ये लाना चाहते हैं, तो उसका नियमावली में प्रावधान है, उसके तहत इन्हें लाना चाहिए लेकिन प्रश्नकाल को बाधित करना अच्छी बात नहीं है महोदय.....(व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

अन्तराल

टर्न–04/कृष्ण/09.03.2016

अंतराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप सदन चलने दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटी है और जेल मैनुअल का उल्लंघन करके राज्य सरकार के मंत्री वहां दरबार लगाते हैं । महोदय, हम उनसे इस्तीफे की मांग किये हैं।

अध्यक्ष : आप विधान सभा के सारे नियम, प्रक्रियाओं से अवगत हैं । अगर आप सही समय पर इस बात को उठाते तो हम सरकार को कुछ कहते भी । लेकिन आपको मालूम है कि कौन बात कब उठायी जाती है और जो बात उठाने का जो समय होता है, वह छोड़ कर सब समय में उठाते हैं । ये तो सदन सुचारू रूप से नहीं चलने का कारण बनता है । हम तो सिर्फ आप से यही आग्रह करेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए आसन को और सभी माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहिए । अगर कुछ भी इस तरह का व्यवधान होता है और सदन नहीं चल पाता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय सदस्यों का नुकसान होता है । सरकार को भी एक तरह से अच्छा होता है कि वह जवाब देने से बच जाती है । इससे माननीय सदस्यों का समय जाया होता है । हम नहीं सोचते हैं कि आप भी ऐसा चाहेंगे । हमारी जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है, उसमें एक से एक गंभीर मुद्दे, गंभीरतम मुद्दे के लिये प्रावधान किया हुआ है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं । इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आ कह

रहे हैं कि मामला गंभीर है । उसके लिये प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान किये गये हैं, उसके तहत उठायें, तभी उस पर कुछ बात भी हो सकती है । आज प्रश्नकाल भी बाधित हो गया तो सदस्यों का समय गया, सदस्यों के प्रश्न थे, ध्यानाकर्षण थे, एक-एक ध्यानाकर्षण के लिए माननीय सदस्य 4-4 बार आते हैं कहने के लिये आसन को कि इसकी स्वीकृति दे दीजिये । ध्यानाकर्षण स्वीकृत होता है परंतु जो व्यवधान होता है, उसके कारण उसे हम नहीं ले पाते हैं । ये सब तो माननीय सदस्यों के हक के खिलाफ है । इसलिए हम आसन की तरफ से यही आग्रह करेंगे कि मामला कितना भी गंभीर हो, हो सकता है कि आप गंभीर बात कह रहे हों, लेकिन हर चीज उठाने का समय निर्धारित है । समय पर उठायेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, मैं आपकी बातों से सहमत हूं । लेकिन महोदय, बहुत वाईटल मुद्दा है । राज्य सरकार के माननीय मंत्री महोदय वहां जाकर दरबार लगाने का काम करते हैं, मीटिंग करने का काम करते हैं । इस तरह की बात से राज्य को छवि धुमिल हुई है । हमलोग यही आग्रह किये थे कि सरकार उनसे इस्तीफा ले ले । उस मामले की हमलोगों ने जांच कराने की मांग की है । इतनी सी बात है, सरकार खड़ा हो कर कह दे ।

अध्यक्ष : माननीय नेता,प्रतिपक्ष । आग्रह करने का भी समय होता है । आप समय पर आग्रह करियेगा, सरकार उसको सुनेगी । अभी तो सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है ।

(इस अवसर पर भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर बोलने लगे)

विभिन्न दलों को सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, उसी में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	:	59 मिनट,
जनता दल (यू)	:	52 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	:	39 मिनट,
इन्डियन नेशल कांग्रेस	:	20 मिनट,
सी0पी0आई0(एम0एल0)	:	02 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	:	02 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	:	01 मिनट,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	:	02 मिनट,
निर्दलीय	:	03 मिनट ।

कुल -180 मिनट ।

प्रभारी मंत्री,शिक्षा । अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च,2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति

के लिये 218,97,02,24,000/- (दो सौ अठारह अरब, सनतानबे करोड़, दो लाख चौबीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(इस अवसर पर भाजपा के सभी मा0 सदस्यगण सदन से बहिर्गमन किये)

अध्यक्ष : शिक्षा विभाग की मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र कुमार सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं और इन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा अनुपस्थित हैं । इसलिए अब जो माननीय शिक्षामंत्री का जो मूल प्रस्ताव है,उसी पर विचार-विमर्श होगा। मा0स0डा0 फराज फातमी ।

डा0 फराज फातमी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं इस सदन में पहली मर्तबा बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसलिये मेरी बात से अगर कोई दिक्कत हो तो हम माफी चाहते हैं । सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं । महोदय,शिक्षा विभाग के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की गयी है मैं उनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं धन्यवाद व्यक्त करताहूं माननीय अध्यक्ष महोदय का और पूरे सदन का । साथ ही साथ, आज जो मुझे शिक्षा के ऊपर बोलने का मौका मिला है,मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो महागठबंधन की सरकार बनी है तो मैं बिहार की तमाम जनता को धन्यवाददेता हूं कि उन्होंने भारी समर्थन के

साथ हमारी सरकार बनाई है और यहां जो माननीय विधायक मौजूद हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसी मजबूत सरकार बिहार के अंदर बनी है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार काक जो सात निश्चय लेकर सरकार चली है जिसको 5 सालों में पूरा क रने का निश्चय है मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । साथ ही साथ,मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट पेश हुआ है,राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर जो बजट हमारे सामने आया है, उसको मैंने पढ़ा था, उसमें शिक्षा के ऊपर जो राशि सरकार को देने जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है,सबसे ज्यादा पैसा जो दिया गया है, वहशिक्षा विभाग को दिया गया है। मैं सरकार को इसके लिये हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनायें देता हूं । साथ ही साथ, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षाविभागमें जो 7 निश्चय है उसके अंदर जो सरकार की नीति है जिसमें आप विधान सभा के सारे नियम, प्रक्रियाओं से अवगत हैं । अगर आप सही समय पर इस बात को उठाते तो हम सरकार को कुछ कहते भी । लेकिन आपको मालूम है कि कौन बात कब उठायी जाती है और जो बात उठाने का जो समय होता है, वह छोड़ कर सब समय में उठाते हैं । तो ये तो सदन सुचारू रूप से नहीं चलने का कारण बनता है। हम तो सिर्फ आप से यही आग्रह करेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए आसन को और सभी माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहिए और अगर कुछ भी इस तरह का व्यवधान होता है तो सदन नहीं चल पाता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय सदस्यों का नुकसान होता है । सरकार को भी एक तरह से अच्छा होता है कि वह जवाब देने से बच जाती हैं । तो माननीय सदस्यों का समय जाया होता है । हम नहीं सोचते हैं कि आप भी ऐसा चाहेंगे और हमारी जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है, उसमें एक से एक गंभीर मुद्दे, गंभीरतम मुद्दे के लिये प्रावधान किया हुआ है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं । इसलिए हम

आपसे आग्रह करेंगे कि मामला गंभीर है, उसको जो अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान किये गये हैं, उसके तहत उठायें, तभी उस पर कुछ बात भी हो सकती है । आज प्रश्नकाल भी बाधित हो गया तो सदस्यों का समय गया, सदस्यों के प्रश्न थे, èयानाकर्षण थे, एक-एक èयानाकर्षण के लिए माननीय सदस्य 4-4 बार आते हैं कहने के लिये आसन को कि इसकी स्वीकृति दे दीजिये । èयानाकर्षण स्वीकृत होता है और जो व्यवधान होता है, उसके कारण वे नहीं ले पाते हैं । तो ये सब तो माननीय सदस्यों के हक के खिलाफ है । इसलिए हम आसन के तरफ से यही आग्रह करेंगे कि मामला कितना भी गंभीर हो, हो सकता है कि आप गंभीर बात कह रहे हों, लेकिन हर चीज उठाने का समय निर्धारित है । समय पर उठायेंगे तो बात आगे बढ़ेगी । (क्रमशः)

टर्न-5/सत्येन्द्र/9-3-16

श्री फराज फातमी(क्रमशः) एक बात तो मैं जरूर कहूंगा इस सदन के अन्दर विरोधी दल के लोग यहां नहीं है। कम से कम यह सरकार जिस तरीके से देश के अन्दर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सेकुलरिज्म का रंग यूनिवर्सिटीज को देना चाह रहे हैं, हमारी सरकार उसको इस बिहार के अन्दर नहीं होने देगी इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से जिस तरीके से रोहित वेमुला जिसने आत्महत्या कर ली यूनिवर्सिटी के अन्दर, जिस तरह से कन्हैया कुमार का हाल हुआ वह हाल बिहार के अन्दर हमारी सरकार नहीं होने देगी। उसको रोकने का काम करेगी और उसको बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी यह हम निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। रही बात आज जो सात निश्चय तय किया है हमारी सरकार ने किस तरीके से स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय

लिया है जिसमें चार लाख रू0 की सुविधा हर बच्चे को लोन के रूप में देने की बात कही है यह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे हमारे वाहर पढ़ने जाते हैं जो गरीब बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है पढ़ाई में कम से कम उनको इस लोन से काफी सुविधा मिल पायेगी। साथ ही साथ जो दूसरी बात है इस सात निश्चय के अन्दर जो बच्चे जिनको काम नहीं मिल पाता है,जो बेरोजगार हैं कम से कम एक हजार रू0 की जो देने का काम करेगी। इसका मैं स्वागत करता हूॅ। यह बहुत बड़ी बात है इससे कम से कम जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी मिलने में फायदा हो पायेगा। साथ साथ जो निश्चय सरकार ने लिया है जिसमें हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी ने जो निश्चय लिया है उसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी हर जिला के अन्दर, एक भोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, एक आई0टी0आई0 की स्थापना होगी। साथ ही साथ जो पांच यूनिवर्सिटीज बनने का निश्चय लिया गया है उसका भी मैं स्वागत करता हूॅ। साथ ही साथ हर पंचायत में,मैं आपको बतलाना चाहता हूॅ, पूरे बिहार में चाहे वो दलित का गांव हो या महादलित का गांव हो,चाहे अति पिछड़ा का गांव हो, हर जगह एक स्कूल जरूर पहुंच गया है बन के तैयार है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूॅ।अब कोई भी टोला या गांव नहीं बचा है जहां स्कूल की स्थापना नहीं हुई है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम बच्चों को जो मिनिमम एजुकेशन चाहिए वो उनको सुविधा मिल रही है। जो आज सरकार बनी है जो पिछली सरकार है उसने एक बड़ा कदम उठाया था वह है बच्चों का स्कौलरशीप जो 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं जिनको अच्छा मार्क्स आता है उनको अगर किसी को स्कौलरशीप देने का काम किया है तो वह हमारी सरकार है और यह बहुत बड़ी बात है। साथ साथ मिड डे मिल जो पूरे बिहार में चल रहा है,चाहे पोशाक वितरण का मामला हो या साईकिल वितरण का मामला हो मैं सरकार का स्वागत करता हूॅ। ये बहुत बड़ी बात सरकार ने की है इससे बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ कि एडुकेशन के अन्दर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर डेवलप हुआ है लेकिन कहीं न कहीं गुणवत्ता में हमारे अन्दर कमी है। आज जो टीचर हमारे पास हैं

वो टीचर अच्छे से ट्रेंड नहीं है उनकी ट्रेनिंग ठीक तरीके से नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो अनट्रेंड टीचर है, कम से कम उनको जरूर ट्रेनिंग करायी जाय। एक गुणवत्ता जो होनी चाहिए टीचर के अन्दर वो तभी आ पायेगी जब टीचर हमारे स्कूल के अन्दर आ पायेंगे और वो सही एजुकेशन हमारे बच्चे को दे पायेंगे । मैं चाहूंगा कि अच्छी एजुकेशन के साथ-साथ गुणवत्ता भी होनी चाहिए। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने पांच यूनिवर्सिटीज खोलने का जो निर्णय किया है जिला के अन्दर मैं चाहूंगा कि जिला के अन्दर भी कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। इससे काफी फायदा होगा उसमें एक चीज और होनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी जगह मुहैय्या होनी चाहिए ताकि उनको भी पढ़ाई करने में आसानी हो सके लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि कई सारे बच्चे यहां से बाहर जाते हैं दिल्ली मद्रास कलकत्ता में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोई कुछ और। होता क्या है कि यहां पर उसकी सुविधा कम है तो मैं यह गुजारिश करूंगा माननीय मंत्री जी से कि एक अच्छा बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे अमेरिका की हो, इंग्लैंड की हो यहां उनको लीज पर जमीन देकर के बुलाया जाय। यहां उसकी स्थापना की जाय। इससे क्या होगा कि उसके अन्दर भी गुणवत्ता को देखते हुए कम से 20-25 सीट उसमें उन गरीब बच्चों के लिए बुक करायी जाय ताकि उनको भी पढ़ाई करने में सुविधा मिल सके। मैं आपसे आह्वान करता हूँ सदन के माध्यम से, रही बात सरकार प्राईमरी और सेकेन्डरी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन आज भी बच्चे का जो अटेंडेंस है उसमें आज भी कमी है उसको हमें देखना पड़ेगा उसमें पैरेंटस की काउन्सिलिंग होनी जरूरी है,पैरेंटस से उनको बुलाकर के कमिटी बनाकर उसको उसमें रखना चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ उपस्थिति भी हो। आज बच्चे को आप स्कौलरशीप दे रहे हैं,मिड डे मिल भी चला रहे हैं फिर भी आज बच्चे पूरी तरह से स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी उपस्थिति की कमी है इसको देखने की

जरूरत है इसको समझने की जरूरत है कि क्या इसमें परेशानी है। साथ-साथ हमारी सरकार प्राईमरी और सेकेन्डरी एजुकेशन में बहुत काम कर रही है लेकिन अभी हमें हायर एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना होगा ताकि उसमें जो गुणवत्ता की जरूरत है वह पूर्ण हो।उसमें अच्छे क्वालिफाई टीचर्स हों, इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने माईनोरिटी एजुकेशन के अन्दर काम किया है यह बहुत बड़ी बात है। आज उर्दू टी0ई0टी0 टीचर की बहाली हो रही है लेकिन अभी भी उसमें कमी है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि सारे टीचर्स की बहाली ठीक तरीके से हो जाय। साथ साथ मदरसा के अन्दर रिफौर्म आना बहुत जरूरी है आज मदरसा का कई जगह भवन बनकर तैयार है लेकिन आज भी टीचर्स की बहाली ठीक तरीके से नहीं हो रही है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,बिल्डिंग की कमी है,लाईब्रेरी की कमी है तो उसमें भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। रही बात जो मजरूल हक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उसकी जमीन उपलब्ध हो गयी है अशोक चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उसके लिए जमीन उपलब्ध करवाया है लेकिन मैं चाहूंगा कि हर जिला के अन्दर एक औफ कैम्पस यूनिवर्सिटी बनना चाहिए ताकि कम से कम बच्चे जो उर्दू माèयम से पढ़ना चाहते हैं,आई0टी0आई0 बी0एड0 करना चाहते हैं वहां आकर के पढ़ सकें। साथ ही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि मानू का रिजनल सेंटर बिहार में हर जगह चल रहा है। दरभंगा में आई0टी0आई0,बी0एड0 उर्दू में पढ़ाई जा रही है और बच्चे वहां उत्तीर्ण हो रहे हैं और जॉब उनको प्राइवेट में मिल रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो ऑफ कैम्पसेज हैं मजरूल हक यूनिवर्सिटी के उसका हर जगह ऑफ कैम्पसेज हों। उर्दू को भी एक ताकत मजबूती देनी चाहिए ताकि उनके भी सेंटर हर जगह खुल सकें ताकि इससे ऊर्द में जो कमी आ गयी है बच्चे उसको पढ़ सकें और उसको हासिल कर सकें। अंत में मैं जरूर बतलाना चाहता हूँ कि यह सरकार यह बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार को आगे बढ़ना है उसकी चाबी अगर किसी के पास है तो वह ज्ञान है, एजुकेशन है और समृद्ध विकसित बिहार होना है और

विकसित राज्य बनना है तो जरूर सरकार ने जो वादा किया है पांच साल हम काम करने जा रहे हैं और शिक्षा के अन्दर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी,उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है निश्चित रूप से इन सात निश्चयों को उन्होंने जो वादा किया है पांच साल के अन्दर में हम इसको हासिल कर सकेंगे। हमारी सरकार ने जो वादा किया है निश्चित रूप से जब हम जायेंगे पब्लिक के रूप में तो हम यह बात सोच कर के जायेंगे कि जो हमारी सरकार ने वादा किया था उसको हम पूरा कर के उतरे हैं और पांच साल के बाद यह सरकार निश्चित रूप से मैं दुआ करूंगा कि आने वाले पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल की सरकार रहे,महागठबंधन की सरकार रहे। आप स्पीकर साहब ने जो मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष: हमने सिर्फ आपको मौका ही नहीं दिया आपने अच्छा बोला भी।

श्री अभय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय,शिक्षा विभाग के बजट के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अभय जी, आज चूंकि कटौती प्रस्ताव पेश ही नहीं हो पाया इसलिए आज माननीय मंत्री जी के मूल मांग का जो प्रस्ताव है तो हमलोग उसी पर विमर्श कर रहे हैं इसलिए आप उसी मांग के संदर्भ में बोलिये।

श्री अभय कुमार सिन्हा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय,सबसे पहले मैं आपके प्रति आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ आपने हमें शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ।

(क्रमश:)

टर्न-6/मधुप/09.03.16

श्री अभय कुमार सिन्हा : ...क्रमशः... अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के माँग का जो प्रस्ताव है, वह जनहित में बिहार के लिए, शिक्षा हित का यह प्रस्ताव है । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो माँग प्रस्ताव रखा है, वह बिहार हित और शिक्षा हित का प्रस्ताव है ।

अèयक्ष : माननीय सदस्य, आपको 10 मिनट में अपनी सारी बात कह डालनी होगी, इसलिये समय का ख्याल रखियेगा ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा समाज की बुनियादी जरूरत है और आज तेजी के साथ बदलते युग में शिक्षा एक ऐसी पूँजी है, शिक्षा से जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा, विकास उसका निश्चित तौर पर सम्भव होगा ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि विगत वर्षों में शिक्षा में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, मैं समझता हूँ कि वह बतलाने की जरूरत नहीं है, वह साफ नजर आती है । आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा के संबंध में बहुत सारी योजनाएँ चलीं, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, जितनी भी योजनाएँ चलीं, जो पहले शिक्षा की स्थिति थी और जो बदलाव आई, यह दर्शाता है कि अभूतपूर्व बदलाव आई है ।

सभापति महोदय, पहले जो शिक्षा में हमारे छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रहती थी, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है । जब विभिन्न योजनाओं

को लागू किया गया सरकार के माध्यम से, तो अभूतपूर्व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति स्कूल और कॉलेजों में आयी । सभापति महोदय, राज्य सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सफल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार को सभी मोर्चा पर आगे ले जाने का काम कर रही है । इसके लिए हम सरकार को अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं । शिक्षा के विकास में राज्य सरकार गम्भीर रूप से सकारात्मक प्रयास कर रही है । सरकार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा हो, कॉलेज शिक्षा हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी स्तरों में बेहतरी कर रही है ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के सफल दिशा-निर्देश में गॉव की सड़कों पर स्कूल ड्रेस में साइकिल चलाती हुई जब लड़कियॉ स्कूल जाती हैं तो मन को मोह लेती हैं । जब स्कूल जाते हरेक गॉव के कस्बों में, जब साइकिल योजना लागू की गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार में साइकिल योजना लागू किये थे तो उस समय भी लोग तरह-तरह की बातें किया करते थे । बातें करते रहे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी, उन्होंने वह लागू किया और जब वह लागू हुआ तो उसका प्रतिफल निकला कि आज गॉव में ही नहीं बल्कि गॉव का जहॉ सबसे निचला पंक्ति बैठा हुआ है, उन गलियों में भी आज साइकिल से हमारे बच्चे बच्चियॉ बेटी जाती हैं । यह एक बहुत बड़ी सोच है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा कि सात जो निश्चय है, आने वाले समय में सात निश्चय में शिक्षा विभाग का जो लिया गया क्रेडिट कार्ड है, आने वाले समय में वह क्रेडिट कार्ड ऐतिहासिक बदलाव लायेगा । ऐतिहासिक बदलाव इस मायने में कि हमारे यहॉ उच्च शिक्षा का जो प्रतिशत है बिहार में, अभी 13 प्रतिशत है । आने वाले समय, साल दो साल में इसमें निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा में प्रतिशत का

बेतहाशा वृद्धि होगी । सभापति महोदय, यह हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड उच्च शिक्षा के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा ।

शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य हुये । सभापति महोदय, आपके माèयम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि गुणात्मक शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने पहल शुरू कर दी है । कदाचार मुक्त परीक्षा की इन्होंने शुरूआत कर दी है । इंटरमीडिएट की अभी परीक्षा हुई, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई । हम समझते हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा पहले भी हुआ करती थी, निश्चित तौर पर कहीं किसी जगह पर कदाचार हुआ करता था लेकिन उसमें जो हमारे होनहार लोग रहते थे, उनकी जो कार्यशैली रहती थी, वह दब जाती थी । दबने का कारण था कि उसमें शिक्षा पर असर पड़ती थी लेकिन आज माननीय मंत्री महोदय का जो सफल प्रयास है, कदाचार मुक्त परीक्षा का पहल किया है इसकी हम बहुत-बहुत सराहना करते हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिना किसी भेदभाव के काम किया है । हमारे विपक्ष के साथी बोलते रहते हैं, बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत ही कठिन होता है । हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो उनकी सोच रहती है, उस सोच पर वे अडिग रहते हैं और उस सोच को धरातल पर उतारने का काम करते हैं । सात निश्चय की जो बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएँ मैं सदन के माध्यम से सुन रहा था । विरोधी दल के साथी बहुत सारी बातें बोल रहे थे लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार की आवाम माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार की जो सात निश्चय है, उसपर बिहार की आवाम निश्चिंत है कि यह सात निश्चय निश्चित तौर पर पूरा होगा । इसके लिए बिहार की आवाम निश्चिंत है । कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे आवाम में नहीं है, आवाम हमारी जानती है कि नीतीश कुमार जी जो निर्णय ले लेते हैं, उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं, निश्चित तौर पर आवाम को पूरा विश्वास है सरकार

में, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में और पूरा भरोसा है कि यह सात निश्चय निश्चित तौर पर हमारे धरातल पर उतरेगी, ये हमारे आवाम को पूर्ण विश्वास है।

सभापति महोदय, साथी हमारे विरोधी दल के बोलते रहते हैं, बोलना अलग बात है । हमारी सराकर की जो सोच है और जिस रूप में शिक्षा विभाग काम कर रहा है और सरकार ने शिक्षा विभाग के बजट पर सबसे ज्यादा रूपया देने का काम किया है, इसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं । निश्चित तौर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए अनेक तरह का प्लान बनाया जा रहा है । राज्य के मेघावी बच्चों को छात्रवृत्ति हो, मैट्रिक जब पास करते हैं तो 10 हजार की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हो रहा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्य के बढ़ते कदम देखकर केन्द्र सरकार राजनीति कर रही है । केन्द्र सरकार शिक्षा विभाग में ही नहीं बल्कि तमाम विभागों में केन्द्रांश की कटौती कर रही है । हम तो कहना चाहेंगे कि केन्द्रांश की कटौती अगर केन्द्र सरकार करती है तो निश्चित तौर पर हमारे विरोधी दल के सदस्य हों या हमलोग पक्ष के सदस्य हों, हमलोग रहने वाले सबसे पहले बिहार के हैं, जब केन्द्रांश की कटौती होती है तो कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में विपक्षी दल के सदस्यों को भी नुकसान पहुँचता है । इसलिये सभापति महोदय, हम आपके माèयम से कहना चाहते हैं कि केन्द्रांश जो केन्द्र सरकार काटती है, बिहार का हक और अधिकार जो काटा जाता है....

सभापति (श्री अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : उसके लिए सदन से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाय, हम आपसे माँग करना चाहते हैं । सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार ।

टर्न–7/आजाद/09.03.2016

श्रीमती एज्या यादव : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ । मैं अपने माननीय वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी जी का और माननीय शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को बधाई देना चाहती हूँ । मैं शिक्षा बजट 2016–17 के पक्ष में अपना विचार रखना चाहती हूँ ।

मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूँ । मैं एज्या यादव बिहार के एक रूरल कन्स्टीच्यून्सी मोहद्दीनगर से फर्स्ट टाईम एम0एल0ए0 हूँ ।

बिहार के लिए 2016–17 के लिए जो बजटीय प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार शिक्षा के विकास के लिए संकल्पित है । मैंने जब बजट को पढ़ा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शिक्षा बजट भारत के दो महान पुरूष के सोच पर आधारित है । महात्मा गाँधी का जो कनसेप्ट था बेसिक एजुकेशन का, उसकी झलक हर जगह दिखती है । साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू का मानना था We can tell the condition of a nation by looking at the status of the women.

हमारी सरकार की जो बालिकायें एवं किशोरियों के प्रति जो अद्भूत योजनायें हैं, वो बिहार के शहर और गाँव के कोने–कोने में दिखती है । जब लड़कियां शान से स्कूल की पोशाक पहने साईकिल चलाते हुए स्कूल की ओर बढ़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में अब women empowerment दूर नहीं है । नारी सशक्तिकरण की ओर बिहार के बढ़ते कदम की खनक से पूरे देश की आम आवाम परिचित है । इसकी चर्चा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बंगलादेश और चाईना में भी होती है ।

Education is not confined to the four walls of class-room. Education does not begin and end with class room. जब

साईकिल चलाती हुई किशोरी छात्राएं स्कूल जाती है, उन्हें जो एक्सपोजर मिलता है और जो कंफीडेंस मिलता है, यह unparalleled है, अतुलनात्मक है । साथ ही साथ जो हेल्थ एंड हाईजीन का स्कीम है, किशोरी छात्राएं में हेल्थ एंड हाईजीन के प्रति अवेयरनेस लाता है और साथ ही साथ उन्हें हमारे कन्ट्री का मिशन ऑफ क्लीनेस ड्राईव, उस ओर लेकर जाता है ।

मुख्यमंत्री छात्र किशोरी स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम बहुत सोच-समझ कर लिया हुआ एक भावनात्मक कदम है । एडोलोसेन्स गर्ल्स स्टूडेंट्स को इससे काफी लाभ मिलेगा और जो हीन भावना ग्रसित होती है एडोलोसेन्स लड़कियां, उनके बारे में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा है, यह वाकई बधाई के पात्र है और यह एक नया

बदलाव लाया गया है शिक्षा बजट में । इसकी हर महिलायें तारीफ करती हैं। एक और नारा जो अभी तक सुनती आ रही थी कि बेटा-बेटी एक समान, मेरा बिहार सबसे महान । इसकी परिभाषा भी इस बार हमारे शिक्षा बजट में दिखती है । चाहे वह साईकिल की योजना हो या पोशाक की योजना हो, छात्रवृत्ति की योजना हो या स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड के । छात्र और छात्राओं दोनों के लिए यह सारी योजनायें हैं और ऐसा नहीं कि केवल पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए यह योजना है । जो उच्च जाति के बच्चे हैं, जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, जो कमजोर परिवार के बच्चे हैं, वो भी अगर प्रथम श्रेणी से पास होते हैं, मेधावी हैं तो उनके लिए भी 10हजार रू0 की प्रोत्साहन राशि है । हमारे यहां शिक्षा बजट में जो प्रावधान है, यह भी कहीं न कहीं महात्मा गॉधी की सोच की ओर ले जाता है । जिनका सपना था कि एक क्लासलेस सोसाईटी को स्टेबलिश करना । सारे बच्चे पढ़ लिख जायेंगे तो एक क्लासलेस सोसाईटी भारत में स्टेबलिश हो जायेगा, जिसमें किसी तरह का एक्सप्लायटेशन नहीं होगा, न सोशल एक्सप्लायटेशन होगा, न इकोनोमिक एक्सप्लायटेशन होगा और हमलोग एक क्लासलेस एजुकेटेड सोसाईटी की ओर बढ़ेंगे।

हमारी अगली योजना स्वच्छ विद्यालय - स्वच्छ भारत के अन्तर्गत जो शौचालय विहिन विद्यालयों में शौचालय का निर्माण करना है, यह बहुत ही अच्छा

और सराहनीय कदम है । खासकर के छात्रा और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने का एक नवीन विचार है । स्वच्छ विद्यालय का जो अभियान है, एक स्वच्छ विद्यालय में पढ़ने के वजह से बच्चों में एक जागरूकता क्लीनेस के तरफ जागेगी और जो स्वच्छ भारत का मिशन है, उस ओर बच्चे बढ़ेंगे । बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता जागेगी । बस स्कूल प्रशासन को ध्यान देना है कि शौचालय की साफ-सफाई, रख-रखाव में ध्यान दिया जाय ताकि हेल्थ एंड हाईजीन बच्चों का मेनटेन रहे ।

महोदय, मिशन गुणवत्ता भी सरकार का बहुत ही सराहनीय योजना है । ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार सिर्फ छात्र और छात्राओं के बारे में ही सोचती है । इनकी सोच शिक्षक और प्रोफेसर के लिए है, वो भी बहुत सराहनीय है । जिस मिशन गुणवत्ता के तहत जो विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, विश्वविद्यालयों में लेक्चरर की बी0पी0एस0सी0 की द्वारा नियुक्ति होगी, इससे क्वालिटी टीचर्स की बहाली होगी, जिनका असर सीधे हमारे स्टूडेंट्स और छात्राओं पर पड़ेगा ।

Effective Teacher Effectiveness in Bihar के तहत टीचर्स के इफेक्टीवनेस को बढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूसंस को स्टैंन्थ देना, बल देना बहुत जरूरी है और यह देखना भी जरूरी है कि सारा पारामीटर और क्राइटेरिया को फुलफील करता हुआ टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूसंस स्टेबलिश हो । टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूसंस में एक क्वालिर्टेटिव चेंज लाने की आवश्यकता है और इस तरह के टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूसंस अगर टीचर निकलेंगे तो वे एक अच्छे टीचर्स होंगे, वे पॉलिस टीचर्स होंगे, वे एक्टीव होंगे, इनथुजियास्टिक टीचर्स होंगे और जेनरल सेनसेटीव होंगे । इस तरह के टीचर जब बच्चों को पढ़ायेंगे तो Teaching will be come in joint experience , बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई से भागते हैं, वह नहीं भागेंगे । उनकी रूचि उनका इन्ट्रेस्ट शिक्षा में जागेगी और उनके लिए टीचिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जायेगा । इफेक्टीव टीचर्स और इफेक्टीवनेस में एक और अच्छी बात है कि टीचर्स को प्रोत्साहित किया जायेगा । टीचर्स को भी प्रोत्साहित

करना बहुत जरूरी है । जब तक टीचर्स प्रोत्साहित नहीं होंगे, उनकी रूचि पढ़ाने में नहीं होगी । एक बार जब उनकी रूचि पढ़ाने में हो जाती है तो इसका सीधा लाभ हमारे छात्र और छात्राओं पर पड़ेगा । अच्छे परफोरमेंस वाले टीचर्स को अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो हमारे एकेडेमिक परफोरमेंस हमारे बच्चों के एकेडेमिक परफोरमेंस में इसका झलक लगेगा । बच्चों में एक इन्ट्रेस्ट और जिज्ञासा जागेगी, उनकी उपस्थिति स्कूल में अपने आप बढ़ जायेगी, वे अपनी मर्जी से स्कूल में आयेंगे और इसका लाभ सीधा बच्चों पर पड़ेगा । शिक्षा के साथ-साथ जो स्कील्ड डेवलपमेंट की योजना है, यह तो बहुत ही अद्‌भूत योजना है, यह भी कहीं न कहीं हमारे महात्मा गॉधी के आईडिया और उनके आदर्श को दर्शाती है । महात्मा गॉधी का मानना था कि Education is in-complete it must be supplemented by some kind skill. उनका कहना था कि ऑल राऊंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी बहुत जरूरी है और यह तभी हो सकता है, अगर बॉडी माईन्ड एंड सोल का डेवलपमेंट हो । बिना ऑल राऊंड डेवलपमेंट के एजुकेशन इज अनकमप्लीट । Education should be supplemented by skill. Education + skill development is complete education . Skill development vocational ट्रेनिंग के रूप में दिया जा सकता है । इससे बच्चे यदि बारहवीं के बाद यदि जरूरत हो, अगर पैसा कमाने की जरूरत पड़ी तो वे अपने पैर पर भी खड़े हो सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं ।

महोदय, सरकार की जो चिन्हित दो स्कीम हैं - कॉम्यूनिकेशन स्कील्स एवं कमप्यूटर स्कील्स, यह बहुत ही सटीक और बहुत ही चिन्हित किया हुआ स्कील्स है। It is not only the need of Bihar but also the need of generation. बच्चे तभी सशक्त होंगे, उनमें कंफीडेंस आयेगी और वे आगे बढ़ेंगे। हमारे बिहार के बच्चे जो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉम्यूनिकेशन स्कील्स बहुत अच्छा नहीं होता, उन्हें कम्प्यूटर नहीं आती है, इस हीनता से वे बाहर निकलेंगे और यदि बारहवीं के बाद उन्हें बाहर जाना का मौका

मिलता है तो वे अच्छे विद्यार्थी साबित होंगे । इन ड्यू रिसपेक्ट शिक्षा मंत्री हम एक-दो सुझाव भी देना चाहूँगी । एक तो हर स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि एकेडेमिक कैलेंडर मेनटेन हो । अगर एकेडेमिक कैलेंडर मेनटेन होगा, स्ट्रीक्टली फौलो होगा, समय पर बच्चों का एडमिशन होगा, एक्जामिनेशन होगा तो समय पर सिलेबस भी कवर कर लिया जायेगा ।

एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे बिहार में ऐसा बहुत इलाका है, जहां माइनोरिटी कॉम्यूनिटी के लोग रहते हैं, लड़कियां रहती है खासकर दलित, अतिपिछड़ा और इन लड़कियां के घर के नजदीक स्कूल नहीं होने के कारण, पर्दा सिस्टम होने के कारण हेजीटेशन के कारण उनके माँ-बाप इन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं तो कुछ ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लेना चाहिए जहां माइनोरिटी कॉम्यूनिटी की छात्रायें और बच्चियां रहती हैं, वहां पर स्कूल खोलना चाहिए ताकि बच्चियों को स्कूल जाने में डिसटेंस की वजह से, पर्दा सिस्टम की वजह से कोई परेशानी नहीं हो ।

शौचालय स्कूल में बन रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय काम है । एक और सुझाव मैं देना चाहूँगी कि हर स्कूल में एक इनफॉरमरी होना चाहिए । जहां खेल-कूद के दौरान अगर बच्चे इन्जर्ड हो जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट ऐड की सुविधा प्रदान होनी चाहिए । अगर ऐसा पौसिबल नहीं है कि हरेक स्कूल में नर्स और ए0एन0एम0 की नियुक्ति हो जाय तो कम से कम चार-पॉच स्कूल जो एक जगह हैं, अगर वहां पर भी एक नर्स की नियुक्ति हो जायेगी तो बच्चों को जरूरत पर फर्स्ट ऐड की सुविधा प्रदान हो सकती है । एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे गांव के स्कूल में खासकर साल में एक बार मेडिकल कैम्प लगाना चाहिए । जिससे बच्चों का एक मेडिकल हेल्थ चेकअप हो सके ईयर, नोज, चेस्ट, आई का। सबसे पहले तो गांव के बच्चे कुपोषित है और ऑख का प्रोब्लम मैक्सिमम बच्चों को वहां होता है । अगर पैरेन्ट्स को अवेयरनेस नहीं है, इकोनोमिकली और फाइनेंसियली वे उतना खर्च नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जा सकें, यदि साल में एक बार भी मेडिकल हेल्थ चेकअप या मेडिकल कैम्प लगता है, इससे बच्चों का चेकअप हो

जायेगा और सरकारी सुविधा से इन लोगों को कुछ विटामिन्स और मेडीसीन भी उपलब्ध करा दी जायेगी ।

..... क्रमशः .....

टर्न-8/अंजनी/दि0 9.3.16

...क्रमशः.....

श्रीमती एज्या यादव : इससे हमारे बच्चे न सिर्फ शि।क्षित होंगे बल्कि आगे चलकर बिहार के बच्चे शिक्षित तो होंगे ही, जिस तरह की हमारी योजनायें हैं और साथ-ही-साथ स्वस्थ भी होंगे । हमारा बिहार आगे चलकर शिक्षित और स्वस्थ्य बिहार के रूप में बढ़ेगा । मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि यह थोड़ा शिक्षा विभाग से हटकर है लेकिन विमेन के स्कील डेभलपमेंट और विमेन के फेभर में है । वर्ष 1992 में बिहार में महिला सामाख्या की स्थापना हुई थी और महिला सामाख्या की जो स्थापना हुई थी, इसकी सुविधा 28 डिस्ट्रिक्टस, 125 ब्लॉक्स और 8000 भिलेज की 4 लाख रूरल पुअर दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी और ई0बी0सी0 एडोलसेंट गर्ल्स चाइल्ड को लाभ मिला था लेकिन बहुत-ही दुःख की बात है कि यह जो सेंटªल फंडिंग से जो चल रहा था, पिछले डेढ़ साल से सेंटªल फंडिंग बंद हो गयी है और महिला सामाख्या की स्थिति अच्छी नहीं है । महिला सामाख्या का मेन मुद्दा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह स्कूल में स्कील डेभलपमेंट कराती थी और कई लड़कियों को जुडो कराटे सिखायी है और साथ-ही-साथ विमेन मजदूरी मिशन की जो ट्रेनिंग होती है, वह भी कराया गया है, जिसके वजह से करीब 60,716 शौचालय का निर्माण हो चुका है । मैं चाहूंगी कि

हमारे मंत्री जी इस ओर ध्यान दे और सेंट्रल फंडिंग से फाइनेंस उपलब्ध कराये ताकि जो 17 डिस्ट्रिक्टस बचे हुए हैं और महिला सामाख्या का काम जो बंद पड़ा हुआ है, वह शुरू हो जाय ताकि हमारी किशोरी, दलित, बैकवर्ड लड़कियां जो हैं, उन्हें फायदा हो । सभापति महोदय, मैं एक महिला प्रतिनिधि हूँ और बिहार की महिलायें उन्नति और स्वालंबन चाहती है । साथ आना शुरूआत होती है, साथ रहने से प्रगति होती है और साथ काम करने से सफलता मिलती है, इसी आशा के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पक्ष और विपक्ष शिक्षा जैसे नाजुक विषय पर एकजुट मिलकर आगे बढ़ेंगे ।

धन्यवाद ।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : एज्याजी, बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह ।

श्री राज किशोर सिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं बजट के पक्ष में आप सब लोगों के सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, कल विपक्ष की ओर से कटाक्ष किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि बिहार में बहार है । मुझे अफसोस है जो विरोध के माननीय सदस्य कल बिहार में बहार है कह कर कटाक्ष कर रहे थे, काश वे आज सदन में होते तो शायद सभापति जी से ज्यादा समय मांगते । उनको बिहार का बहार नजर नहीं आता है, इसलिए नजर नहीं आता है कि जो कल तक बिहार के लोग और इस देश के लोग कल्पना नहीं किये थे, वह सब आज बिहार में दिखायी पड़ रहा है । आज झोपड़ी में, झोपड़ी के वैसे बच्चे और ऐसी बच्चियां साईकिल से फर्राटा लगाते हुए सड़क पर चलती है तो यह उनको दिखायी नहीं पड़ता है । इसलिए दिखायी नहीं पड़ता कि वे कभी सोचे नहीं थे कि इस घर के मां-बाप जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, उसके बच्चे भी मैटिªक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे ? दलित बस्ती में, पिछड़े बस्ती में, अल्पसंख्यक बस्ती में

उनकी निगाह कभी नहीं जा रहा था और वहां की बच्चियां, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चियां भी पढ़ती हैं, मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती है, उनकी खुशी का एहसास उनके दिल में नहीं होता है । कभी वे कल्पना तो किये नहीं कि इस घर में कभी एक दिन रोशनी आयेगी । माननीय नीतीश कुमार जी के होने से आज वहां भी रोशनी है, जहां सदियों से अंधेरा था । सभापति महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कार्यक्रम आज बिहार में चल रहा है, न उसमें कोई जात है और न कोई धर्म है । साईकिल कार्यक्रम सभी के लिए है, उंच-नीच, स्वर्ण, पिछड़ा दलित सभी के लिए है । उसी तरह पोशाक का कार्यक्रम सभी के लिए है, उसमें न कोई जात है, न कोई धर्म है । सब का साथ-सब का विकास, कहने वाले क्या किये ? जिस युवा के बदौलत सत्ता में आने का काम किया वर्ष 2014 में दिल्ली की सरकार, आज युवा के साथ क्या करने का काम किये ? मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुखिया होता है किसी सरकार का, जिसको आपसे बहुत अपनापन है, उस पद पर रखने का काम मत कीजिए । आप उनको कहीं रखिए न, जो देश के लिए अच्छा हो, राज्य के लिए अच्छा हो, वैसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर रखने का काम कीजिए । न कि ज्यादा अपनापन है तो ऐसा कुर्सी पर रख दीजिए जो देश को गलत रास्ते पर ले जाने का काम करता हो । आपको बहुत अपनापन था प्रधानमंत्री, कोई कुर्सी आप दे देते, कोई काम दे देते लेकिन वैसे आदमी को कदापि रखने का काम नहीं कीजिए, जिससे देश का सिर झुकता हो । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, जिस युवा के बल पर सत्ता में आने का काम किये प्रधानमंत्री, आज वही युवा के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है । चाहे जोधपुर हो, चाहे पुने का इन्स्टीच्यूट हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो । आज इस देश का गौरव है जे0एन0यू0 । जे0एन0यू0 गौरव है, सभापति महोदय, उसने इस देश को आई0ए0एस0,आई0पी0एस0,आई0एफ0एस0 दिया है लेकिन आज जे0एन0यू0 को बदनाम किया जा रहा है । किसके साजिश पर जे0एन0यू0 को बदनाम किया जा रहा है, लगता है कि दिल्ली का राज दिल्ली से

नहीं, नागपुर से संचालित होता है । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उनको बेमुल्ला के दर्द का एहसास नहीं है लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूँ सदन से माèयम से कि आप एक बेमुल्ला को मजबूर कर दिया मरने के लिए लेकिन इस देश के 25-30 करोड़ बेमुल्ला परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा । याद रखियेगा, सत्ता के नशा में मगरूर मत होइए, हिटलर और मुसोलिनी की राह पर भारत में जहां मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां धर्मनिरपेक्षता है, वहां पर आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते । मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि कल मैं भाषण सुन रहा था, विरोध के एक माननीय साथी कह रहे थे कि रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गये न उबरे, मोती मानुस चुन । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके यही पंक्ति रहिमन की यही वाणी माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचा दीजिए । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि टी0भी0 पर मैं एक दिन देख रहा था, इस देश का महान क्रिकेट खिलाड़ी अभी विराट कोहली है, कह रहे थे कि जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा । पता नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे थे या किसके लिए कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम । लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर प्रधाानमंत्री जी के लिए कह रहे थे, शायद ऐसा नहीं है तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ - जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा । साथियों, मैं आपको कुछ और बतलाने से पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और कृतत्व को न सिर्फ बिहार जानता है बल्कि पूरा देश और दुनिया जानने का काम करती है । आज इस देश में ही नही, दुनिया में माननीय नीतीश कुमार जी ने वादा और विश्वास पर खड़ा उतरने का जो आदर्श कायम किया है, इसके सब लोग कायल हैं । हमारी सरकार का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी और लालू यादव हमारे नेता जो सामाजिक न्याय के हैं, हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार और इस सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं । हमारे लाजवाब शिक्षा मंत्री, बेहतरीन शिक्षा मंत्री साबित करने का काम किया । पिछले दफे एकाध सेंटर पर गड़बड़ी हुई, दुनिया में हमारी जरूर बेइज्जती हुई, बदनामी हुई, ऐसा मैं महसूस करता

हूँ लेकिन आज इस देश और राज्य के लोग देख रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी को, कहीं चर्चा तक नहीं होती कि कैसे ये परीक्षा करा रहे हैं । मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि जो इनका और इनकी सरकार का जो सात निश्चय है, यह सामान्य बात नहीं है, समझने का चीज है, विकास इसी सात निश्चय से निकलेगा ।

क्रमश:.....

टर्न–9/शंभु/09.03.16

श्री राजकिशोर सिंह : क्रमश:.....और जो ये भारत की सरकार सिटी बनाने का काम करती है, सपना देखती है। पता नहीं सिटी का सपना जुमला है या सच्चाई है, लेकिन सात निश्चय जिस दिन पूरा हो जायेगा तो गांव भी सिटी होने का काम करेगा, गांव भी सिटी बनने का काम करेगा। मैं कुछ निश्चय के विषय में बताना चाहूंगा, जो हमारी सरकार करने जा रही है। सभापति महोदय, 1 हजार रूपया प्रतिमाह बेरोजगार को दो साल तक देने का काम हमारी सरकार करेगी। 4 लाख रूपये तक का क्रेडिट कार्ड– जिस गरीब के घर में 1 लाख रूपया कर्ज नहीं मिलनेवाला है, उसके तरफ कभी इनका अहसास होता है? 1 लाख रूपया कोई कर्ज नहीं देता है गांव में, लेकिन आज 4 लाख क्रेडिट कार्ड लेकर के वह आगे की पढ़ाई कर सकता है। इस कार्यक्रम की विशेषता समझने का शायद समझ नहीं रखते थे लोग। जो सिनेटरी नैपकिन की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है उसका कितना महत्व है, समझने की जरूरत है। जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्नीक कॉलेज ये जब बन जायेगा, इससे जो लाभ होगा यह समझना और अहसास करने की चीज है। वाई फाई की सुविधा सभी युनिवर्सिटी में होने का काम होगा। साथ ही मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा सरकार से मैं महसूस करता हूँ कि जो सरकारी विद्यालय में

पढ़ाई होनी चाहिए, शायद नहीं होती है। उसमें और कुछ करने की जरूरत है और हम आशा और विश्वास करते हैं, हम अपने काबिल शिक्षा मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि उस तरफ इनकी निगाह जायेगी और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में चारों ओर हम विकास करेंगे। साथ ही मैं वैशाली से आता हूँ, वैशाली लोकतंत्र की धरती है, इन्टरनेशनल प्लेस है और मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर निश्चित रूप से एक डिग्री कॉलेज अथवा मेडिकल कॉलेज- इस तरफ घ्यान दें ताकि वहां की बच्चियां जो 60 कि0मी0, 70 कि0मी0 गरीब की बच्ची कैसे हाजीपुर, कैसे मुजप्फरपुर पढ़ने जायेगी। वहां एक डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करती तो मुझे खुशी होती। साथ ही जो कॉलेज में फैकल्टी का अभाव है, स्कूल में फैकल्टी का अभाव है उस तरफ हमारे काबिल शिक्षा मंत्री जरूर घ्यान देंगे। इसी के साथ मैं बजट के पक्ष में अपनी बात समाप्त करते हुए सबको आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूँ।

सभापति (श्री अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा।

श्री अजीत शर्मा : इस सत्र में पहली बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं जिस जनता ने अपार बहुमत से महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जीत दिलायी। मैं अपनी तरफ से और तमाम महागठबंधन के साथियों के तरफ से जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हमलोगो को सरकार सौंपा है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने सूबे की बागडोर 2005 में संभाली तब से शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के मामले में एक गुणात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जब से शिक्षा मंत्री जी ने कार्यभार संभाला है तो इनकी सोच शिक्षा के प्रति ये बहुत जार्गरूक हैं, इनका भी हम आभार प्रकट करते है। चूंकि मीडिया के माध्यम से इनकी हर चीज पढ़ने को

मिलती है और सदन में भी बातें सुनने को मिलती है। वित्तमंत्री जी ने जो बजट बनाया- नवम्बर में महागठबंधन की सरकार बनी और इतने कम दिनों में बजट तैयार करके इन्होंने बजट में जो अभी प्रावधान किया 1 लाख 44 हजार करोड़ रूपये का 2016-17 का बजट पेश किया गया, यह काबिले तारीफ है। इतने कम दिनों में बजट तैयार करके सदन में पेश करना यह बहुत ही बड़ी बात है, इनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूॅ। ये जो बजट बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय को केंद्रित करते हुए बनाया गया जिसमें कि बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार के उपाय करने की बात कही गयी है। 12वीं कक्षा पास छात्र-छात्राओं को जो गरीब घर से आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको क्रेडिट कार्ड 4 लाख रूपया देने की बात कही गयी है। इनका भी मैं सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूॅ। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उच्च शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान किया गया है 21897 करोड़, जो 15.13 परसेंट है। यह बहुत ही बिहार के शिक्षा के लिए कम है। इसमें सुधार की जरूरत है चूंकि इतने कम बजट में मेरा मानना है कि जो शिक्षा की स्थिति पूरे बिहार में वह पूरी नहीं हो पायेगी और जो शिक्षा मंत्री जी की सोच है- वह शायद समझते होंगे इन बातों को- जो कि बहुत कम है। नियोजित प्राथामिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 जुलाई, 2015 से निर्धारित वेतनमान देने का जो निश्चय हुआ है, यह भी एक साहसिक कदम है। इसपर भी मैं धन्यवाद देता हूॅ। मुख्यमंत्री पोशाक योजना जो पहले से ही मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं 1 से 8 वर्ग के बच्चों के लिए, पोशाक बहुत छोटी चीज नहीं है, उससे एक समानता स्कूल में नजर आती है, यह नहीं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, उससे हीनता की भावना खत्म हो जाती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो

इन्होंने पोशाक योजना शुरू करायी उससे सारे ूस्कूल में बच्चे डिसिप्लीन एक तरह के लगते है। मुख्यमंत्री बाल साइकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत राज्य के विद्यालयों में 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल दी जाती है और अभी भी दिया जा रहा है। जब लड़कियां साइकिल पर सवार होकर अपने स्कूलों के तरफ जाती हुई नजर आती है तो अनायास लोग कहते हैं कि इस सामाजिक परिवर्तन के वाहक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए जनता उनको और अपनी तरफ से भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। शिक्षा के विकास के बिना बिहार का विकास असंभव है। शिक्षा ऐसे एक विभाग है, लेकिन हमारा मानना है कि शिक्षा के बिना बिहार के विकास की कल्पना करना ही बेकार है। इसलिए शिक्षा जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। चूंकि आज जो अपराध है, आज जो गरीबी है, आज जो समाज में समानता नहीं है यह शिक्षा के कमी चलते लोग कहते हैं। सभी माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं यहां गरीबी है, अशिक्षा है, दलित लोग रहते हैं निश्चित तौर पर अगर शिक्षा में सुधार हो जायेगा तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि शिक्षा के बल पर ही बिहार आगे बढ़ सकता है। इसलिए शिक्षा पर माननीय मंत्री तो खुद जागरूक हैं, मैं उनको चाहूंगा कि कुछ बिन्दुओं पर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या-क्या जरूरी है, कुछ हमारी भी सोच है। जो सभापति महोदय आपके माघ्यम से हम बताना चाहेंगे। प्रशासन की भूमिका भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है और समाज की भी भूमिका होती है। तभी शिक्षा आगे बढ़ सकता है जब शिक्षक एवं छात्र विद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए समय पर आयें। इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत है, एक नियम बनाने की जरूरत है। उसके लिए कुछ सुझाव हमारे

हैं जैसे कि बायोमिट्रिक सिस्टम से एटेंडेंस, सिर्फ स्कूल के शिक्षक का ही नहीं महाविद्यालय के शिक्षक और स्टाफ का भी चूंकि एटेंडेंस बनने से एक सिस्टम बनता है, पूरे विश्व में, पूरे देश में हर जगह बायोमिट्रिक सिस्टम लगा है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं है। मैंने उदाहरण स्वरूप भागलपुर में दो स्कूलों में बायोमिट्रिक सिस्टम और सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने का काम किया है और वहां से शिक्षा मंत्री को कुछ पता भी होगा नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि 9 बजकर 25 मिनट पर सभी शिक्षक लाइन लगाकर बायोमिट्रिक सिस्टम पर एटेंडेंस बनाने के लिए वे जागरूक रहते हैं। इसका विरोध भी हुआ भागलपुर में, लेकिन उनको यह समझाने की जरूरत है कि बायोमिट्रिक सिस्टम उनको डराने के लिए नहीं है, उनको चूंकि समाज में एक मैसेज है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं आते, पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए बायोमिट्रिक सिस्टम के द्वारा आपका रेकार्ड होगा कि आप समय पर आते हैं और समय से स्कूल से जाते हैं तो समाज में एक मैसेज जायेगा इसिलए इसको भी करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा विथ भ्वाइस रेकॉर्डिंग सभी क्लास रूम में चाहे स्कूल हो या कॉलेजेज हो शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं वह रेकार्ड होगा.....क्रमशः।

टर्न–10/अशोक/09.03.2016

श्री अजीत शर्मा : क्रमशः .. कभी– कभी शिक्षकों की गलती होती है, चूंकि आप जानते हैं कि 50 प्रतिशत शिक्षक हमारे स्कूल में ऐसे है जो पढ़ाने के काबिल नहीं है, जो नौकरियां हुई,कुछ गलतियां हुई हैं, 50 प्रतशित शिक्षक वैसे हैं जो नहीं जानते हैं तो सी.सी.टी.वी. कैमरा विथ वायस

रिकार्डिंग्स से बहुत सारे फायदे हुये हैं, स्कूलों में विगत दो महीना में, माननीय शिक्षा मंत्री को हम धन्यवाद देंगे कदाचार मुक्त परीक्षा जो इन्होंने सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाकर करने का काम किया है, इससे कदाचार बिल्कुल रूका है । जहां तक हम अपने जिला भागलपुर की बात करते है, वहां कदाचार का उदाहरण नहीं आया होगा । पूरे बिहार में कदाचार नहीं हुआ है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते है । सी.सी.टी.वी. कैमरा जब रिर्काडिंग के साथ होगा तो प्रिंसपल अपने चैम्बर से स्क्रीन पर सभी क्लासों का मौनेटरिंग करेगें कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी जब देखेगा कि सब कुछ दिख रहा है तो बच्चे भी सतर्क रहेंगे । सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि पूरा ऑन लाईन सिस्टम करके, आप, सरकार भी यहां से किसी स्कूल की स्थिति के बारे में जानना चाहे कि वहां क्या पढ़ाई हो रही है, मकान की क्या स्थिति है, जर्जर है या सही है, सरकार यहां से जानकारी ले पायेगी । इससे शिक्षा का स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा । आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर पोस्टेड हैं, औचक निरक्षण की कमी है, चूंकि उनको यह लगता है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है । वहां एस..डी.ओ., डी.एम0 साहब हों, जो भी पदाधिकारी शिक्षा मंत्री समझे , निरीक्षण निश्चित तौर पर होना चाहिए ताकि शिक्षा आगे बढ़ सके ।

बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसकी आरे भी आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । वर्ग के हिसाब से क्लास रूम नहीं है, आप देखियेगा कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया साईकल और पोशाक की राशि, खासकर के छात्रायें आकर्षित हुई है शिक्षा के प्रति । हमारे यहां एगजाम्पुल के तौर पर बालिका उच्च विद्यालय है, 2493 छात्रायें वहां पढ़ती हैं । पहले, 2005 के पहले यह संख्या चार सौ कुछ थी, चूंकि आज शिक्षा में आकर्षण पैदा हुआ है, इसलिए वहां 2493 बच्चियां, वहां कमरे की कमी है, शिक्षक की कमी है, अगर हमारे माननीय मत्री, शिक्षा मंत्री जी शिक्षक की कमी को पूरा करे दे और जो अन्य रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर दें । कमरे

की कमी है, वहां बरामदा पर बैठकर पढ़ती है, 2493 में 16 शिक्षक है, 10 कमरे हैं मात्र, कैसे बच्चियां पढ़ती है, बरामदे में पढ़ती है छात्राओं को मैं क्रेडिट देता हूँ, इतनी कमी के वाबजूद भी स्कूल आती हैं और शिक्षा ग्रहण करती है । हम इस ओर इनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। स्कूलों में कम से कम एक स्मार्ट क्लास रूम होना चाहिए । स्मार्ट क्लास रूम की आज जरूरत है, वह पूरी सुसज्जित होना चाहिए, प्रोजेक्टर, स्क्रीन होना चाहिए, कम्प्यूटर होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए- वहां पर स्टडी मटेरियल्स होनी चाहिए स्मार्ट क्लास रूम में ताकि एक मैसेज जाय कि हमारे सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास भी हैं ।

तीसरा है, लाईब्रेरी तो है, लाईब्रेरियन भी हैं, वहां पर एक सिस्टम यह बनाना होगा कि शिक्षक वहां स्टूडेंट के साथ प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो घंटी लाईब्रेरी में बच्चों को सामने बैठाकर निश्चितइ तौर पर उसका अध्ययन करें इससे छात्राओं को लाभ मिलेगा । शिक्षा मंत्री को आपके माध्यम से बतलाना चाहेंगे, प्रत्येक विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी का था सफाई शौचालय बनाने का- छात्राओं के लिए अलग एवं छात्र के लिए अलग, निश्चित तौर पर बने हैं लेकिन साफ-सफाई की बहुत कमी है, बिल्कुल साफ नहीं रहता है इसके लिए मैं आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि सफाईकर्मी की वहां कमी है, अगर शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान दें, एक-एक सफाईकर्मी की नियुक्ति प्रत्येक स्कूल में कर दें तो शौचायल भी स्वच्छ रहेंगा और जिनको नौकरी नही मिली है उनको नौकरी भी मिलने का काम करेगा । इस ओर आप ध्यान देना चाहेंगे । महीनें में एक बार, हम चाहेंगे, कि शिक्षक अभिभावक और अगल-बगल के प्रबुद्धजन हैं उनके साथ एक बैठक आयोजित हो, निश्चिततौर पर एक पदाधिकारी शिक्षा विभाग या प्रशासन का मौंजूद रहे ताकि सारी जानकारी सरकार को मिल सके ।

आज हमारे यहां पढ़ाई जो स्कूलों में होती है प्रथम वर्ग से होती है । प्रथम वर्ग में सीधे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पर पढ़ाई शुरू कर देते है। हम आग्रह करेंगे कि वहां के.जी. क्लास भी होना चाहिए, इसलिए कि पहले बच्चों में, स्कूल जाने की आदत पहले लगानी

पड़ती है, इसके बाद पढ़ाई का बोझ उस पर पड़ता है । हम चाहेंगे कि के.जी. क्लास से स्कूलों में पढ़ाई हो ताकि बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा ।

दूसरा है कि हमारे यहां अंग्रेजी की पढ़ाई छठे क्लास से शुरू होती है तो इस कारण बच्चे प्रथम क्लास से पांचवी क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, इसक कारण वे समझ नहीं पाते हैं, इस कारण उनका बेस कमजोर होता है । तो हम सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि प्रथम क्लास से एक सबजेक्ट जो अंग्रेजी का है, वह शुरू हो ताकि बच्चों का बेस मजबूत हो और भविष्य में अंग्रेजी की पढ़ाई कर सके ।

जहां तक कम्प्यूटर की पढ़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सभी स्कूलों में करीब-करीब कम्प्यूटर की सप्लाई भी हुई थी और पढ़ाई शुरू करने की बात की थी, लेकिन बड़ा दु:खद है कि वहां शिक्षक के अभाव में सारे कम्प्यूटर बेकार पड़े हैं, खराब पड़े हैं । उसका कोई यूज नहीं है और बिना कम्प्यूटर के आज शिक्षा में आगे बढ़ना, सोचना ही बेकार है इसलिए आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे, संज्ञान में डालेंगे कि निश्चित तौर पर कम्प्यूटर की पढ़ई क्लास थ्री से निश्चित तौर पर हो ताकि हमारे बच्चे भी देश में और विश्व में नाम कमा सके । इसलिए कम्प्यूटर की पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के युग में ।

शिक्षकों का घोर अभाव है, शिक्षक के अभाव के बार में सब लोग बोलते हैं लेकिन बिना शिक्षक के तो बड़ा मुश्किल है स्कूल चलना। सदन में बहुत बार बोल चुके हैं, इसलिए शिक्षक का अभाव है, चूंकि बच्चे और बच्चियां आपकी ओर देख रही है, पूरी जनता देख रही है, शिक्षकों को भी निश्चित तौर पर देने का काम करेंगे ।

हमलोग जो परीक्षाफल देते हैं, प्राईवेट स्कूल में हम जो परीक्षाफल जो देते हैं, वह भी स्कूल में रेकार्ड हो, बच्चे और गार्जियन को सामने बुलाकर परीक्षाफल दिया जाय ताकि गार्जियन भी समझ सके कि बच्चे क्या और कैसा कर रहे हैं- इसको करने की जरूरत है ।

सूबे की जनता माननीय मुख्यमंत्री पर यकीन रखती है साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री पर भरोसा करती है कि आप शैक्षणिग जगत में जो परिवर्त्तन का प्रयास कर रहे हैं वह अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहनण करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, आज मैं सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा लाये गये प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, यह सर्वव्यापी है कि शिक्षा के बगैर समाज के विकास की कल्पना भी करना मिथ्या होता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को बतलाना चाहता था लेकिन गरीबों के मुद्दा पर, जहां शिक्षा एक अहम सवाल है किसी समाज और विकास के लिए या फिर देश के स्तर पर या समाज के स्तर पर विकास के लिए शिक्षा अहम भूमिका रखती है । आज सदन में शिक्षा के वाद-विवाद में विपक्ष का भाग जाना बिहार की जनता के साथ बेईमानी साबित हो रहा है,

महोदय, हम इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि आज हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, हम ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में शिक्षा के महत्व को हम जानते नहीं थे । माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जब वह शब्द हमारे कानों तक पहुंचा- एक जूता सिने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले पढ़ना-लिखना सिखो- यह बात तब आया था, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों का, आपके द्वारा ही तो, यह निश्चित तौर पर इतिहास गबाह है कि आपके द्वारा जब शिक्षा और धनुर्विद्या भी लेने का अधिकार भी इस समाज के निचले कड़ी के लोगों को नहीं था । जब धनुर्विद्या लेने की बात आती है तो फल के साथ अंगूठा कटवा लिया जाता है । क्रमशः

टर्न-11-09-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री राजेन्द्र कुमार : मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रतिपक्ष में शिक्षा जैसे अहम सवाल पर लोग गंभीर नहीं है जबकि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा के सवाल पर गंभीर रुप धारण करने पर आज विपक्ष को निश्चित तौर पर तमाचा लगा है। वह नहीं चाहते थे कि गरीब का बेटा पढ़ लिखकर आगे आवे । उनकी मंशा यह नहीं थी कि गरीब का बेटा पढ़ लिखकर सदन तक आये , वह नहीं चाहते थे कि पढ़- लिखकर गरीब का बेटा दफ्तर तक जाये । इसलिए मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहूँगा कि आज विपक्ष सदन में नहीं है । मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन करने की दिशा में आप काम किए हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि देश की गरीब जनता जिसके बदन पर कपड़ा नहीं था , जब विद्यालय के लिए निकलता था और जब धनिक वर्गों के शरीर पर नये कपड़े दिखते थे , स्कूल का ड्रेस दिखता था और गरीब के बच्चे फटेहाली हालत में विद्यालय जाते थे , वे अंदर से आत्महीनता का शिकार होते थे और आत्महीनता का शिकार होने की वजह से वह पढ़ाई में दक्षतापूर्ण पढ़ाई नहीं कर पाते थे । हम निश्चित तौर पर आज के दिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी , माननीय तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को और आज के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी को कि निश्चित तौर पर जो हालात था , जो फेटेहाली हालत थी जिससे हम निकल कर आए हैं । ये जंगल राज की बात करते हैं , मैं इनको बतलाना चाहता था कि जंगल राज का यह गरीब का बेटा आजँ खड़ा है जिस गरीब का, जंगल राज का परिभाषा उनकी

थी, गरीबों का राज ॅ- जिसमें शिक्षा नहीं हो, जिसमें फटेहाली हालत हो उसको गरीबों का राज कहते थे और जंगल राज कहते थे । आज जंगल का राज जंगल से निकल करके आज लालू यादव की देन है कि जंगल से निकाल करके यह दलित का बेटा , गरीब का बेटा , अल्पसंख्यक का बेटा, अति पिछड़ों का बेटा सभी स्तरों पर अव्वल स्थान रखने का काम करता है । मैं बतलाना चाहूँगा कि आज सदन क माध्यम से महोदय, कि आज देश के हर कोने से आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हालात महिलाओं की थी इनके द्वारा मनुस्मृति माना जाता है , बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर को नमन करता हूँ कि निश्चित तौर पर कि अगर संविधान में यह समाहित नहीं होता शिक्षा के समान अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं होता तो यह जंगल राज कहने वाले हम सबों को जंगल में ही डाल कर छोड़ देते , शिक्षा से ें जुड़ने कभी नहीं देते । हम बतलाना चाहेंगे और निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि आज प्रतिपक्ष के लोग जो हालात पैदा किए थे शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा मनुस्मृति माना जाता है , बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधानिक अधिकार को निश्चित तौर पर दबाने का प्रयास मनुस्मृति के माèयम से किया जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा , माननीय तेजस्वी जी के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देकर आज यह साबित कर दिया गया है और जिन प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा यह बात लिखी गयी थी कि नारी, शुद्र शिक्षा नहीं हो यह मनुस्मृति में यह उल्लिखित कराये थे ये नहीं चाहते थे कि देश की नारी शिक्षा के क्षेत्र मे जायं , ये नहीं चाहते थे कि देश के शूद्र , अति पिछड़ा शिक्षा के क्षे्त्र में जांय । ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं । इसलिए मैं; आज आपके माध्यम से बतलाना चाहते हैं और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर महागठबंधन को उसकी सारी नीयति को जिसकी कथनी और करनी एक समान है । यह समझते हुए यहाँ की जनता ने मैनडेट देने का काम किया है । लेकिन उनको जो आज भाग

खड़े होते हैं बिहार की जनता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं रखा तो आज निश्चित तौर पर जब बिहार के विकास की बात आती है , बिहार में शिक्षा का माहौल पैदा करने की बात आती है तो आज सदन से भाग खड़े होते हैं। वाद–विवाद में भी खड़ा होन के लायक बिहार की जनता उनको नहीं छोड़ी है।

महोदय, निश्चित तौर पर हम आपके माध्यम से सदन से कहना चाहते हैं कि यह देश जिस हालात में है , इस देश में गरीब के बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे कि '' बच्चों के छोटे हाथों से चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों से चांद सितारे छूने दो – चार किताबें पढ़कर वह भी हम जैसे हो जायेंगे , वह भी हम जैसे हो जायेंगे । '' प्रतिपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जो माहौल पैदा हो रहा है जिसको आज ये कहते हैं और उस संबंध में हम निश्चित तौर पर आपके माध्यम से इनको बतलाना चाहते हैं कि महागठबंधन विद्यालय का शाब्दिक अर्थ मानती है विद्यार्थी , निपुण शिक्षक , जागरुक अभिभावक और अच्छी पढ़ाई – इसका ही मतलब अच्छा विद्यालय होता है । जिसका उदाहरण है कि आज देश सराह रहा है । आज देश में सराहना हो रही है । आज पूरे बिहार के लोग यह समझ गए हैं कि निश्चित तौर पर महागठबंधन जो कहती है वह करती है । आज शिक्षा मंत्री के द्वारा जो इन्टर की परीक्षा में कदाचार मुक्त परीक्षा ली गयी है, आज बिहार में वह एक वार्ता और बिहार में एक चर्चा का विषय बन गया है । हम बतलाना चाहेंगे विपक्ष के लोगों को कि आप जो चाहते हैं जो महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना चाहते थें , आज शिक्षा के साथ साथ पचास परसेंट आरक्षण देकर रोजगार का भी सृजन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है । हम बतलाना चाहेंगे कि आज के दिन जो साईकिल पर चढ़कर हमारे समाज की बच्चियॉं निकलती हैं , एक दिन हुआ करता था , हम स्वयं इस चीज का उदाहरणस्वरुप हैं जब मैं पैदल आठ किलोमीटर चलकर विद्यालय जाता

था और वहाँ से फिर पैदल चल कर आता था । आज मेरे घर की बच्चियाँ पैदल चलने की वजह से शिक्षा से कोसों दूर रह गयीं लेकिन हमारी सरकार आज शिक्षा से जोड़ते हुए महिलाओं के प्रति इतनी सजग हुई कि यह साईकिल चलाकर आज बिहार में महिलाओं को, आधी आबादी को इस देश में इस बिहार में इनके द्वारा साजिश के तहत चौखट के अंदर दबाकर उनकी ताकत को रखा गया था, हमारी सरकार बिहार में उस ताकत को उभार कर इस बिहार को सबल करने का काम किया है । जब देश में आधी आबादी को दबा दिया जाय आप अंदाजा करते हैं कि ये विकास की बात करते हैं। ये विकास की बात करते हैं और आज ये अपराध की बात करते हैं तो मैं बतला दूँ कि निश्चित तौर पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा अगर शिक्षा का अलख नहीं जगाया गया होता तो यह बिहार नक्सलवाद हो गया रहता , नक्सलवाद हो गया रहता । इसको कोई रोक नहीं सकता था । ये कहते हैं कि अपराध बढ़ा है , मैं चाहूँगा इस सदन से कि अगर जाँच करा दी जाय तो जो जंगल राज की बात करते हैं और इशारा करते हैं कि खास जाति के पास तो आज जितने भी अपराध हुए हैं, अगर उसकी सही जाँच करा दी जाय तो इनके लोग अपराध कर रहे हैं । सरकार को बदनाम करने के लिए इनके लोग अपराध कर रहे हैं , महागठबंधन के लोगों द्वारा यह काम नहीं किया जा रहा है । मैं कहना चाहूँगा और एक निन्दा प्रस्ताव इस सदन में लाना चाहूँगा एक विषय पर । महोदय, अभी आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी की परीक्षा हो रही थी , आन्ध्र प्रदेश जहाँ भाजपा शासित राज्य है , हम चाहेंगे सदन से इस मामले पर गंभीर होने की बात है कि जहाँ जात वाद पर, माननीय लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं । आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी की परीक्षा हो रही थी और उस परीक्षा में जातवाद-जातीय राजनीति खतरनाक है -इसपर ऐसे लिखने के लिए यह क्वेश्चन में समाहित होकर आता है । हम जानना चाहेंगे और इस सदन में निन्दा प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि आज बच्चों

की पढ़ाई में आज परीक्षा में क्वेश्चन में लाने का काम किए भाजपा शासित राज्य आन्ध्र ⁄ प्रदेश में क्वेश्चन में लाते हैं ,प्रश्न में लाते हैं कि जातीयवाद, जातीय राजनीति खतरनाक है । ये क्या जनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सौरी हम, जातीय आरक्षण खतरनाक है , सौरी जिनके द्वारा यह क्वेश्चन लाया गया है कि जातिगत आरक्षण खतरनाक है , आखिर ये करना क्या चाहते हैं ? निश्चित तौर पर ये आरक्षण को खतम करना चाहते हैं । नहीं चाहिए आरक्षण । मैं भी कहता हूँ और मैं इस समर्थन में हूँ कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है । लेकिन शिक्षा , समान शिक्षा लागू कीजिये और आर्थिक विषमता दूर कीजिये और आरक्षण की आवश्यकता नहीं है । आप आन्ध्र प्रदेश जहाँ आपकी सरकार है , महोदय, मैं कहना चाहूँगा ये भाजपा के लोगों से कि अपनी जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ विद्यालय में प्रश्न में यह लाते हैं कि यह जातीगत आरक्षण खतरनाक है इसपर ऐसे लिखो । जब लेख लिखने की बात आयेगी हमारे देश के भविष्य नौजवानों के दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा , आरक्षण के प्रति इनकी क्या सोच है , इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं । हम निश्चित तौर पर आज के दिन हम कहना चाहेंगे अपनी सरकार के विषय में कि हमारी सरकार आज मैट्रिक और इन्टर पास करने के बाद, बी0ए0 पास करने के बाद नौकरी तलाश के लिए हम गरीबों के पौकेट में पैसा नहीं हुआ करता था , पैसा के अभाव में आवेदन आवेदित नहीं कर पाते थे

नौकरियों के लिए तो आज दो वर्षों तक 1 हजार रुपया देकर निश्चित तौर पर सरकार ने सराहनीय काम किया है । मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसको सराहता हूँ । क्रमशः

टर्न-12/विजय/ 09.03.16

श्री राजेन्द्र कुमार: क्रमश: .. साथ ही सरकार के द्वारा हायर टेकनोलौजी की पढ़ाई करने के लिए गरीब बच्चों को पैसा उपलब्ध नहीं होता था लेकिन आज किसान के जो बेटे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रू0 उपलब्ध कराने का काम किया है । निश्चित तौर पर बिहार की जनता सरकार के प्रति आभारी है । निश्चित तौर पर यह सरकार और यह मंत्रालय गरीबों के हित में किसानों के हित में काम कर रहा है । यह काम बी0जे0पी0 वाले कभी नहीं किये और इनको खलता है, ये कभी चाहेंगे भी नहीं कि ऐसा काम हो । सभापति जी, हम कहना चाहेंगे, एक सलाह भी होगा मेरी तरफ से माननीय मंत्री जी को निश्चित तौर पर आज शैक्षणिक गुणवत्ता की बात है । विद्यालयो में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों से अलग रखा जाय इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी । हम आग्रह भी करेंगे सरकार से कि जितने भी विद्यालय हैं शिक्षकों को गैर सरकारी कार्यक्रम से अलग रखा जाय । इन कार्यक्रमों से अगर उनको अलग रखा जाता है तो बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा समय लगायेंगे, इससे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी । हम यह भी आग्रह करना चाहेंगे कि सभी विद्यालयों में जब कार्यालय का काम होता है तो एक शिक्षक हमेशा परमानेंट डिस्टर्ब होते हैं कार्यालयों के कामों से, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सभी विद्यालयों में लिपिक की बहाली हो जो केवल कार्यालय का काम करे बाकी शिक्षक शिक्षण कार्यो में लगकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावें । हम इन बातो को रखते हुए आग्रह करेंगे और पुन: बी0जे0पी0 वालों को कहेंगे कि मेरी सरकार गठबंधन की सरकार बिहार के हित में काम कर रही है। आज देश की जनता, बिहार की जनता कराह रही है कराहती रहेगी। अभी ये बिहार से भगाये गये हैं, इस बार देश से भगाये जायेंगे । इसे कोई रोकने वाला नहीं है । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री अशोक कुमार): माननीय सदस्य, श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री बशिष्ठ सिंह: सभापति महोदय, शिक्षा बजट के पक्ष में वाद विवाद में सत्ता पक्ष के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । महोदय, जब बिहार का नेतृत्व पहली बार करने का परम आरदणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मिला नवम्बर, 2005 में उस समय से लेकर आज तक शिक्षा में गुणात्मक विकास और तरक्की हो रहा है । एक समय था कि विद्यालय भवन कहीं पर नहीं हुआ करता था । एक समय था कि बहुत छोटे छोटे गांवों में विद्यालय नहीं हुआ करता था । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो छोटे छोटे कस्बों का जो गांव था वहां नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया गया था । जहां भवन का अभाव था मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में वहां भवन बनवाने का काम किया गया । मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत करने का काम सरकार ने किया । प्राथमिक विद्यालय में जहां बच्चों की संख्या ज्यादा थी उसे मध्य विद्यायल में परिणत कर के किया गया । उस समय जो हमारे गरीब समाज के लोग थे जिनकी बच्चियां पांच तक पढ़ने के बाद जब उसकी उम्र बढ़ जाती थी, उसका शरीर विकसित हो जाता था तो गरीब लोग पढ़ाने में असमर्थ हो जाते थे, उसको कपड़ा देने में असमर्थ हो जाते थे । हमारी सरकार ने एक रणनीति के तहत सभी छात्राओं को पोशाक देने का काम किया । इसलिए कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर था और उसमें भी गरीबी और अमीरी की बातें हो जाया करती थी । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा में गुणात्मक विकास करते हुए एक ड्रेस में सभी बच्चे और बच्चियों को स्कूल भेजने का प्रयास किया जिसका नतीजा है कि आज हमारे बिहार के गरीब के भी बेटा और बेटी विद्यालयों में पढ़ने जा रही हैं। 8 तक पढ़ाई करने के बाद जब हाईस्कूल की बात आती थी 5 कि0मी0, 6 कि0मी0, 7 कि0मी0 की दूरी पर एक उच्च विद्यालय हुआ करता था । बच्चियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी । माननीय मुख्यमंत्री के बुद्धि और विवेक का परिणाम हुआ कि 9 क्लास में जो बच्ची जाएगी उसको साइकिल हम देने का काम करेंगे । जब बच्चियों को साइकिल

देने का काम किया सरकार ने तो बच्चियों में उत्साह जगा और एक ड्रेस पहनकर के जब एक गांव से साइकिल पर उड़ान लेती थी गरीब की बेटी तो बिहार के लोग ही नहीं, हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व के लोग सोचते थे कि बिहार में अजूबा काम सरकार ने किया है । आज उसका परिणाम देखने को मिलता है । इतना ही नहीं किया गया और एक विकास का काम किया गया । बच्चियों के लिए जो बच्ची मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डीवीजन में पास करेगी उसको 10 हजार रू0 का मेगा पुरूस्कार देने का काम सरकार ने किया । जो बेटी मायुस रहती थी उसको अंदर से जुनून जगा, जोश आया कि हम भी बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन में पास करेंगे ताकि सरकार का जो पुरूस्कार है 10 हजार रू0 का हम भी पुरूस्कार लेने का काम करेंगे । आज शिक्षा में गुणात्मक काम हो रहा है । इसके बाद सभी उच्च विद्यालय को 10 प्लस टू करने का काम किया गया। आज विद्यालय में गांव की बच्चियां इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव से पढ़ने का काम करती है । और जब बच्चे लोग भी साइकिल के लिए उदास होने लगे तो सरकार ने बच्चों को भी साइकिल देने का काम किया । आज हमारे बिहार की छात्र एवं छात्राएं उड़ान भर रहे हैं लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ लिखकर के बिहार के जो मेधाावी छात्र होते हैं जब बिहार से बाहर जाते हैं तो दूसरे राज्य के लोग जब परीक्षा देने जाते हैं नौकरी के लिए तो दूसरे राज्य के लोग लाठी डंडा से भगाने का काम करते हैं । केन्द्र की सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रहती है । चाहे वह हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो कोई एक्सन नहीं लेती । लेकिन बिहार के नौजवान को हम कहना चाहते हैं महोदय इस सदन के माध्यम से कि बिहार के छात्रों को कहां कहां पीट कर भगाइयेगा । कितने लोगों को देशद्रोह में डालियेगा । जे0एन0यू0 में कन्हैया को जो देशद्रोह के केस में फंसाये इसका परिणाम क्या होगा, आने वाला वक्त बतायेगा। ये बिहार के लोगों को लाख देशद्रोह के मुकदमें में फंसायें, लाठी से पीट कर भगाइये ये भागने वाले लोग नहीं है। बिहार की मिट्टी उर्जावान मिट्टी है, बिहार की मिट्टी शक्तिशाली है । मैं तो कहता हूं कि दूसरे राज्य की बात छोड़ दिया जाय

अगर नौकरी की बात आए अगर चांद पर भी रिक्तियां निकलेंगी चांद पर भी नौकरी की बात आएगी तो बिहार के छात्र चांद पर जायेंगे । अगर फर्स्ट डीविजन मार्क्स की बात होगी, डिसटिंक्शन मार्क्स की बात होगी तो बिहार के छात्र लायेंगे । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग अनावश्यक सदन को डिस्टर्ब करते हैं, वेल को डिस्टर्ब करते हैं, क्वेश्चन आवर मे लोगों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं । फिर बीच बीच में भाग जाते हैं । हम तो रहते तो एक क्वेश्चन करना चाहते कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी और उनके शिक्षा मंत्री स्मृति इरानी जी का कंपीटीशन करा दीजिये किसी भी मामले में अगर मेरा मुख्यमंत्री और मेरा शिक्षा मंत्री दो कदम आगे नहीं निकले तो हमारे जैसे लोगों को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं ।

(व्यवधान)

महोदय, शिक्षा के सवाल पर मैं बोल रहा हूं । महोदय, जब वे शिक्षा मंत्री बनी तो उस समय एक बात आयी थी कि देश की शिक्षा मंत्री का सर्टिफिकेट मैट्रिक का है कि देश के शिक्षा मंत्री का सर्टिफिकेट इंटर का है । अभी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ओरीजनल सर्टिफिकेट कौन है, इंटर वाला है कि मैट्रिक वाला है ।

क्रमशः

टर्न-13/बिपिन/09.3.2016

श्री वशिष्ठ सिंह: क्रमश: अभी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ऑरिजिनल सर्टिफिकेट कौन है- इंटर वाला है कि मैट्रिक वाला है लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री का सर्टिफिकेट ऑरिजिनल है, कहीं भी दिखाइएगा तो एक नम्बर पर रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा के सवाल पर एक-दो सुझाव हमारा होगा । पहला सुझाव यह है कि इंग्लिश को, अंग्रेजी को कंपलसरी बनाया जाए चूँकि अंग्रेजी में बच्चों की पढ़ाई कमजोर होने के कारण इंटरमीडिएट के बाद बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको परेशानी होती है । दूसरा चीज है महोदय कि यह जो बी.एड. कॉलेज है, एक लाख, अस्सी हजार, दो-दो, ढ़ाई लाख रूपया लेकर लोग ऐडमिशन करते हैं । गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा ? जिस गरीब के बेटा के पास दो लाख रूपया नहीं होगा तो वह कॉलेज में ऐडमिशन नहीं लेगा । इसलिए इस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए । हम कहना चाहते हैं कि यह जो मध्याह्न भोजन है उसके लिए जाते हैं विद्यालय में, लेकिन उस मध्याह्न भोजन में हेडमास्टर को जो सान दिया गया है, हेडमास्टर के मध्याह्न भोजन और व्यवस्था करने में काफी परेशान और तंग-तवाह होने के कारण विद्यालय में पठन-पाठन की क्रिया में कमी आ रही है । इसलिए इससे भी उनको अलग किया जाए । महोदय, जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय बिहार के छोटे-छोटे बच्चे 6वर्ष से लेकर 14वर्ष की उम्र वाले जो बच्चे थे, 12परसेंट स्कूल से बाहर रहते थे । लेकिन आज आपके बच्चे मात्र 0.86ही बाहर रहते हैं । तमाम बिहार के गरीब-गुरूवा का बच्चा आज पढ़ने का काम कर रहे हैं । इसलिए मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में कबूतरा व्याससूक्त माध्यमिक प्लस-टू विद्यालय, कोचस रोहतास जिला में पड़ता है । वहां मैं अपने क्षेत्र के इलाके का भ्रमण कर रहा था । तो कई लोगों का कंप्लेन आया, लिखित आवेदन भी मिला, उस लिखित आवेदन के आधार पर जब मैं उक्त विद्यालय में गया, मोनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए तो वहां का हेडमास्टर असंसदीय भाषा का उपयोग करने का काम किया

जिसका आवेदन मेरे पास है जिसे मैंने विभाग को दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है । हम माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि वैसे हेडमास्टर को जिसका नाम है अशोक कुमार प्रभाकर, वह प्रभारी हेडमास्टर है और वहां 10प्लस- टू का विद्यालय है, सब कुछ हो गया है, कहते हैं कि हम यहां 10प्लस-टू का पढ़ाई नहीं होने देंगे । बाजाप्ता दरखास्त के साथ मेरे पास आवेदन पड़ा हुआ है । हम चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको हटा कर वहां परमानेंट प्राधानाध्यापक दिया जाए और कई हमारे क्षेत्र में उच्च विद्यालय हैं, जहां प्रभारी ही लोग चलाते हैं, हेडमास्टर के रूप में काम करते हैं । एजुकेशन काफी कम है और इंटरमीडिएट हो गया है इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी जगहों पर प्रभारी हटा कर वहां पूर्ण जो प्राधानाध्यापक हैं, उनको रखने का प्रयास किया जाए ।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जब हम जिला परिषद के सदस्य थे, तबसे हम चिल्ला-चिल्ला कर बोलते आ रहे हैं । प्राथमिक विद्यालय,पथलपुरा जो करगहर ब्लॉक में है, प्राथमिक विद्यालय, भेतरामपुर, प्राथमिक विद्यालय, कोनया, प्राथमिक विद्यालय, तिलकापुर, प्राथमिक विद्यालय, प्रयागपुर, इन तमाम विद्यालयों में आठ साल से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है लेकिन जमीन के विवाद में आज तक भवन नहीं बन पाया है । हम लाख 20सूत्री की भी बैठक में उठाते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई । माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, महोदय, आपके माध्यम से कि इस पर कार्रवाई करके विद्यालय को बनाया जाए ताकि वहां के बच्चों का पठन-पाठन सुचारू रूप से चल सके ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे उच्च विद्यालय 10प्लस-टू के हैं जिनमें मकान बन कर तैयार है, खिड़की, जंगला के अभाव में, प्लास्टर नहीं हुआ है और विद्यालय की स्थिति जर्जर है । हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि उक्त विद्यालय में, उच्च विद्यालय कोचस है, उच्च विद्यालय, चिताव है, उच्च विद्यालय, बरमसिया है, उच्च विद्यालय, बिहिया है, उच्च विद्यालय,सन्हौता है, उच्च विद्यालय, विसोडिहरी है, यह तमाम सरकार के पैसे से बन गया है और थोड़े- से पैसे के अभाव में 8-8 बिल्डिंग इसी तरह से पड़ा हुआ है और वहां पठन-पाठन नहीं हो पा रहा है । इसलिए हम निवेदन

करना चाहेंगे आपसे कि इन विद्यालयों को विद्या का केन्द्र बनाने का प्रयास करें ताकि उसमें पठन-पाठन का काम हो सके ।

अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहना है कि हमारे क्षेत्र में सच्चिदानन्द सामुदेव महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में 18एकड़ भूमि है, हम चाहते हैं कि वहां एक बी.एड.कॉलेज का निर्माण कराया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को पढ़ने में सुविधा हो सके । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद । नमस्कार ।

श्री मो0 आफाक आलमः सभापति महोदय, आज सदन के माध्यम से आपने शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आभारी हैं । आज शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार जो काम की है शिक्षा के क्षेत्र में, गांव-गांव में लोगों में एक लहर छाया हुआ है । हर छात्र-छात्राएं और बच्चियां जो हैं, स्कूल जाने लगी है और स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के माध्यम से उनके माता-पिता भी काफी खुश हैं, खुशहाल नजर आते हैं । इसलिए हम कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे आग्रह करते हैं कि जो आज शिक्षा को बढ़ाए हैं, और भी उसको बढ़ाने की जरूरत है । शिक्षा को आगे लाने की जरूरत है । इससे आवाम में काफी जागरूकता आयी है, खुशी की लहर आयी है और बच्चे और बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो उसके माता और पिता के चेहरे पर मुस्कान नजर आता है और आज शिक्षा के माध्यम से बच्चे और बच्चियों को जो छात्रचृति मिल रही है स्कूल में, उससे भी काफी खुशी का लहर छायी हुई है । लोगों में उत्साह जगी है । हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ावें, लेकिन यहां सरकार का जो नियम बना है और जो आधार है, जिस तरह से पढ़ाई का सिस्टम है, उस सिस्टम में थोड़ी सुधार की जरूरत है और हमको उम्मीद है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी काफी इसमें सजग हैं और बहुत सुलझे हुए भी हैं और माननीय सदस्य की बात को भी सुनते हैं । हमने कई बार अपने क्षेत्र की बात रखी है, उस बात को सुन कर उस काम को भी वे किए हैं । लेकिन यहां यह कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं अभी, जो पड़े हुए हैं । जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि वहां

हेडमास्टर की कमी है, प्रभार नहीं दिया जाए । यह बहुत जरूरी है कि अगर हेडस्टमास्टर प्रभार वाले रहेंगे तो वो लोग गुणवत्तार्वूक पढ़ाई नहीं करा सकेंगे और प्रभारी के रूप में वे रहेंगे । इसलिए प्रभारी जहां हैं तो हमारे हर स्कूल में एक हेडमास्टर की जरूरत है, तो जरूर उनको बहाल किया जाए और हर स्कूल में दिया जाए । दूसरी तरफ, आज जो सरकार की तरफ से यह आवाहन चला है कि उत्क्रमित हाई स्कूल बनाया गया है, बहुत जगह स्कूल बन गई है, मकान भी बन रहा है लेकिन उसमें शिक्षक की कमी है । हम माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि उसमें जितना जल्द-से-जल्द हो, शिक्षक देने का काम करें ताकि हमारे बच्चे बच्चियों की पढ़ाई बाधित न हो । इसलिए हमारी मांग है कि और ऐसे जो स्कूल हैं, जैसे, गढ़बनैली हाई स्कूल में भी प्रभार में शिक्षक हैं, जलालगढ़ में हैं, कसबा में भी हैं, तो वहां से प्रभार वाले को हटा कर परमानेंट हेडमास्टर दिया जाए और अभी हमारे मध्य विद्यालय में भोजन का जो कार्यक्रम हो रहा है, मिड-डे मिल का, उसमें बहुत सारे शिक्षक-हेडमास्टर किरानी बन गए हैं और वे किरानी की तरह काम करते हैं । स्कूल के तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता है । बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई भी बाधित होता है और हेडमास्टर ही जब वहां जिम्मेदार हैं तो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से वे निभा नहीं पा रहे हैं । इसलिए हेडमास्टर को फ्री किया जाए और हर स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए किरानी अलग से बहाल कर दिया जाए । यह मेरा एक सुझाव है और इस पर हम उम्मीद है कि अमल किया जाएगा और आग्रह भी है कि हर स्कूल की व्यवस्था को भी देखा जाए । जैसा हमारे कई सदस्य अभी बोले हैं, आपका भी घोषणा है कि हर स्कूल में कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक सिस्टम के हिसाब से उसकी उपस्थिति देखी जाएगी और वहां कैमरा लगाया जाएगा कि कितने समय में वे आते हैं । यह बहुत ही अच्छी चीज है ताकि उसके दिल में यह दहशत हो कि हमको समय पर जाना है और पढ़ाई करना है ... क्रमशः

टर्न–14/राजेश/9.3.16

श्री मो0 आफाक आलम, क्रमशः- और उसका सी0डी0 भी बने कि कौन शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इसपर भी ध्यान देने की जरुरत है। आज लोगों में एक लहर है बच्चों को पढ़ाने का, लोगों में उत्साह है लेकिन यही पर एक अफसोस की बात है कि आज हमारे बच्चे और बच्चियॉं पढ़ने से बाहर जा रही हैं, इसपर खास तौर पर गार्जियन के दिल पर जो गुजरता है वह एहसास का, वे परेशान है कि हम दूसरे राज्यों में बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यह कन्वेंट स्कूल जो खुला है, वह इस कन्वेंट के माध्यम से हो रहा है, काफी लोगों से चार्ज लिया जा रहा है, इसका कोई मापदंड नहीं है लेकिन वह आपके यहॉं से स्वीकृति लेता है और प्राइवेट कन्वेंट स्कूल चला करके ऐसे मनमाने ढंग से चलाते हैं जिसमें अगर गार्जियन भी चाहेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसका इतना लंबा–चौड़ा फीस रहता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, चूंकि वह हमारे राज्य में है और हमारे ही राज्य के लोगों को वे शोषण कर रहे हैं,इसपर आज ध्यान देने की जरुरत है, बड़े–बड़े उच्च विद्यालय इसतरह से वे खोले हैं और वे ट्रस्ट के माध्यम से वे चला रहे हैं, यह बहुत ही जरुरी है, उसपर भी हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं सभापति महोदय का कि जो ट्रस्ट का उच्च शिक्षा है, जो मेडिकल कॉलेज है, जो आई0टी0आई0 कॉलेज हैं, वहॉं सब कॉलेजों से ज्यादा फीस रखा गया है, काफी फीस रखा गया है, उस फीस का कोई अंदाजा नहीं है, वहॉं पर मनमाने ढंग से बच्चों का शोषण हो रहा है, उसमें किसी का भी नहीं चलता है और वह अकेले अपना राज–पाट चलाना चाहते है, वे अपने ढंग से अपना फीस रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन जो गरीब हैं, वे उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वे अपने बच्चे को वहॉं पढ़ा सके, तो मजबूरी में वह बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, तो यह सब जो है, वह

हमारे यहाँ से परमिशन ले लेता है और वे चला रहे हैं, उसमें हमलोगों के बच्चों का, हमलोगों का शोषण हो रहा है, जो पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, तो हम इसपर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इसका मापदंड की जानकारी सभी आम लोगों को होनी चाहिए और सब लोग इसको जानें कि किसका क्या फीस है और वह फीस उसी हिसाब से, अगर गार्जियन सक्षम हो, तो वह देकर अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं भी अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं लेकिन आज उनको दर-दर भटकना पड़ रहा है, आज हमारे बच्चे कोटा में और अन्य दूसरे राज्यों दिल्ली में आकाश वगैरह जो खोला है, उसी तर्ज पर हमारे राज्य में भी खोला जाय ताकि हमारे जो लोग सक्षम होंगे, उस तर्ज पर अपने बच्चों को पढ़ा पायेंगे और उसके बच्चे की पढ़ाई और उसका भविष्य बनेगा, तो इसतरह कि सब सुविधा की जरुरत है। आज बहुत सारे स्कूल भवनहीन हैं, जो भवनहीन स्कूल हैं, उसमे जितना जल्द से जल्द हो, भवन बनाया जाय, चूंकि आज बच्चों और गार्जियन में जो उत्साह जगा है पढ़ाई-लिखाई का, हम स्कूल के अध्यक्ष हैं, हम सब स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, वे बहुत सारी बात को हमलोगों के सामने रखते हैं, अपनी कमी को रखते हैं,उस कमी को हमलोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ झूठा वादा भी कर देते है, कहीं-कहीं पर हमलोगों से बुलवा भी लिया जाता है कि आपलोग यह मकान को कब तक बनवा दीजियेगा, शौचालय कब तक बना दीजियेगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द बनाया जाय और गुणवत्तापूर्वक जो है, वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। सभापति महोदय, माननीय श्री लालू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, एक समय ऐसा था, जिस समय वे अपने राज्य में, अपनी हुकूमत के वक्त, लागू किये थे कि जो भी शिक्षक बनेंगे, वे कमीशन से आयेंगे और कमीशन से जो भी शिक्षक उस समय बहाल हुए थे, उनसे

गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई भी होती थी और लोगों में एक खुशी भी होती थी, इसलिए गुणवत्तापूर्वक आज बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए कि आज हर इंसान के लिए बच्चों का भविष्य होता है और बच्चों के भविष्य के लिए हर गार्जियन हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बने लेकिन आज जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे के अंदर गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई तो होती है लेकिन गरीब के बच्चे के अंदर गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई नहीं हो रही है, यह बात जो है हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्वक बेस लाइन जो नीचे से उपर लाया गया है, जो निचले स्तर से लाया गया है, वहॉं से उसको गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सभापति महोदय की आज जो वे एक्जाम लिये हैं, उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मारा, एक भी शिकायत सुनने को हमलोगों को नहीं मिला, आज अगर हमारे शिक्षा मंत्री जी टाईट हो गये, तो पूरे बिहार का काया ही बदल गया और आज आम लोगों के जुवान पर तारीफ होने लगी, शिक्षा का गुणगान होने लगा लेकिन गुणवत्ता को जड़ से लाने का प्रयास करेंगे नहीं करेंगे प्राईमरी स्कूल से और प्राईमरी स्कूल से जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, तो गुणवत्तापूर्वक हमारे स्कूल में इसका पढ़ाई होगा लेकिन आज हमारे कई ऐसे शिक्षक है जिन्हें बहाल करना जरुरी है, जो आपके भी नॉलेज में होगा, हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि शिक्षकों का बहाली किया जाय और जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है, उन सभी शिक्षकों को बहाल कर दिया जाय और पदोन्नति वाले, जो हमारे पूर्णियां प्रमंडल के चार जिला हैं, उन चार जिला में कटिहार और किशनगंज में तो पदोन्नति वाले शिक्षकों की बहाली हो गया है लेकिन हमारे पूर्णियां जिले में पदोन्नति वाले शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, उसको अविलंब बहाल किया जाय, दूसरी तरफ 35,540 शिक्षक जो हैं, उनको भी बदली किया जाय, उसका पोस्टिंग किया जाय, इन

सबों की भी मांग है कि शिक्षक लोगों का जो होना चाहिए, वह हो और यह बहुत जरुरी है।

दूसरी बात यह है कि प्लस टू में जहॉं-जहॉं शिक्षक नहीं हैं, वहॉं अविलंब शिक्षक को भेजा जाय और वहॉं प्लस टू की पढ़ाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ आज डिग्री कॉलेज की मांग हमारे कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, डिग्री कॉलेज का होना बहुत जरुरी है, जिसतरह से आपने मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करने का काम किया है, आपने इसे पंचायत स्तर तक देने का काम किया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि जो आपकी सोच है, वह बहुत ऊंचा सोच है, अभी हमारे माननीय कई सदस्य बोले कि पहले हमारे बच्चों को 5 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था हाईस्कूल में, जिसके कारण हम उन बच्चों को संसाधन के साथ नहीं भेज पाते थे लेकिन आज हर बच्चे बच्चियों को इतना दूर नहीं जाना पड़ रहा है और यह सरकार का ही देन है, इसके लिए हम सरकार को बधाई देते है, सरकार के इस सोच को हम बधाई देते हैं, यह बहुत ही ऊंचा सोच है, आज स्थिति ऐसी है कि हर घर के बगल में स्कूल खुल गया है और आज बच्चों को बहुत सुविधा हो गया है, आज जो बच्चे मैट्रिक पास कर गये, वे अपने बच्चों को हाईस्कूल में आराम से पढ़ा सकते हैं, उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आज डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में खोल दिया जाय, इससे उसका परेशानी दूर हो जायेगा और हमारे श्रीनगर प्रखंड में एस0सी0/एस0टी0 कोटा में इसको लिया जाय, वहॉं उसको अपनी जमीन है और एस0सी0/एस0टी0 के जो लोग हैं, वह सरकार के नजर में भी गरीब है, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि वे गरीब हैं, वह आगे तक नहीं जा सकेगा, तो अगर वहॉं पर डिग्री कॉलेज खुल जाता है, वहॉं पर एस0सी0/एस0टी0 का पोपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहॉं पर डिग्री कॉलेज खोला जाय, अगर वहॉं

पर डिग्री कॉलेज खुल जायेगा, तो गरीबों को पढ़ने में आसानी होगी, उसको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को कि हमारे यहॉ बी0एड0 की पढ़ाई नहीं हो रही थी लेकिन ट्रेनिंग स्कूल जो श्रीनगर में है, वहॉ पर करोड़ों का मकान बन रहा है, वहॉ पर मकान बनने से, वहॉ के लोगों को काफी खुशी मिली है कि वहॉ पर अब बी0एड0 की पढ़ाई शुरु होगी, अब लोग बाहर नहीं जायेंगे, यह सब उपलब्धि जो है, वह हमारी सरकार का है और यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है और माननीय शिक्षा मंत्री जी का है, इसके लिए हम खासतौर से यह कहना चाहते हैं कि यह बहुत ही आम चीज है, जो पिछली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कमी को समझें कि मदरसा का जो छठा वेतन था, उसको वे लागू किये, वे दिये, इससे उनलोगों के बीच काफी खुशी का लहर हुआ है और वे चुनाव में खासतौर से हमारे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, वे सारे लोग एक जुट हो करके अपना मत देने का काम किया है, इस सरकार की उपलब्धि पर, इस सरकार के काम पर खुशी होकर एक जुट होकर मतदान किया लेकिन मेरा आग्रह सरकार से होगा कि उनके छठा वेतन में कुछ कमी है, उनके छठे वेतन को अविलंब पूरा किया जाय, जब आप एक तरफ स्कूल को यह मान्यता दिये हैं कि स्कूल का और मदरसे के बच्चों का दोनों का डिग्री एक समान है तो मदरसे के शिक्षको को भी एक समान वेतन होना चाहिए, मेरा आग्रह होगा कि एक समान वेतन मदरसों के शिक्षकों को भी दिया जाय और उनका जो पेंशन है, उसको भी लागू किया जाय, चूंकि वे बेचारे जब रिटायर करते हैं, तो वे दर-दर भटकते हैं, वे अपने लोगों से मोहताज रहते हैं, इसलिए हम मांग करते हैं इस सदन के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि उन शिक्षकों को भी पेंशन लागू किया जाय, उनको भी पेंशन मिले और यह उनके बुढ़ापे का एक सहारा होगा और यह होना बहुत

ही जरुरी है और उनको स्कूल के तर्ज पर वहॉ मकान भी दिया जाय, बेंच कुर्सी भी दिया जाय.....(व्यवधान)

सभापति (श्री अशोक कुमार):- अब आप समाप्त करें।

श्री मो0 आफाक आलम:- महोदय, यह सब हमारी मांग है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो हमारी मांग है, उसपर सरकार विचार करें और सरकार को भी हम धन्यवाद देते है और माननीय सभापति महोदय जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

टर्न : 15/कृष्ण/09.03.16

सभापति (श्री अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईस्लाम शाहीन ।

श्री अखतरूल ईस्लाम शाहीन : माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम तमाम लोग जानते हैं कि शिक्षा मानवता के लिए वरदान है और हमारी सरकार शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण समझ कर काम कर रही है, शिक्षा हमारे बिहार में आज नहीं बल्कि हजारो साल पहले आदि काल से ही बहुत गौरवशााली बिहार का इतिहास रहा । यहां नालन्दा जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशीला जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां न केवल बिहार के न केवल भारत वर्ष की बल्कि पूरी दुनियां के लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करते थे । आज बिहार सरकार को चुनौती यही है कि पुराने गौरवशाली इतिहास को कैसे प्राप्त किया जाय । आज बिहार की जो आर्थिक स्थिति है और जो संसाधन का अभाव है, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । आज बिहार में जितने भी टोले हैं, जितने भी बसावटें हैं, प्रत्येक बसावट के

एक किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय के संकल्प को लेकर यह बिहार सरकार चली है और लगभग 99 प्रतिशत सफलता हमें मिल चुकी है और लगभग एक टोले, एक बसावट के 3 किलो मीटर के अंदर मèय विद्यालय को लक्ष्य करके यह सरकार चली, उसमें भी लगभग 99 प्रतिशत सफलता मिल गयी है और एक लक्ष्य को लेकर बिहार सरकार चल रही है कि प्रत्येक पंचायत में भी उच्च विद्यालय हो ताकि हमारी बच्चियां जो दूर तक नहीं जा पाती थी, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नहीं जा पाती थी, इस लक्ष्य को भी लेकर बिहार सरकार आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि 2000 से अधिक मèय विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाया जा चुका है और कुछ ही दिनों में प्रत्येक पंचायत में भी एक उच्च विद्यालय खोलने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा ।

सभापति महोदय, कम संसाधन के बावजूद 21 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालय हमारे बिहार में खोले गये और 20 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित कर मèय विद्यालय बनाया गया और 11 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के भवन का निर्माण भी कर लिया गया और इसी कम संसाधन के बावजूद 2 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय के कमरों का भी निर्माण इस बिहार में किया गया है । यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है । इसके लिए पूरी सरकार बधाई के पाात्र है और जो स्थिति आर्थिक रूप से बिहार की है, हम तमाम लोग भली-भांति जानते हैं । उसके बाद भी पोशाक की राशि लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों को केवल इस वित्तीय वर्ष में दिया गया और छात्रवृत्ति की राशि 2 करोड़ बच्चों को केवल इस वित्तीय वर्ष में दिया गया । इन राशियों को अगर हम जोड़ेंगे तो अरबों-खरबों में जाता है । उसके बाद जो साईकिल योजना चली, साईकिल में लगभग 20 लाख बच्चों को बच्चियों को साईकिल दिये गये । यह भी अरबो-खरबों में जाता है । साईकिल योजना तो ऐसा क्रांतिकारी काम किया जैसाकि पूर्व साथियों ने भी बताया कि निश्चित रूप से यह केवल उसके मनोबल को ही नहीं बढ़ाया बल्कि एक वरदान साबित हुआ । पहले जो बच्चियां अपने घरों से नहीं निकलती थी,आज उनको अपना निर्णय लेना आ गया, वे अपने घरों से निकलती हैं, चौक पर जाती हैं, टैफिक सिस्टम को समझती हैं और वह निर्णय लेती है कि दायें जाना है, बायें जाना है, सड़कों पर कैसे चलना

है, उसमें एक आत्मविश्वास विकसित हुआ और वह बड़े-बड़े निर्णय लेने के लिये सक्षम हो गयी । इसी तरह विभिन्न योजनाओं में जो उच्च विद्यालय हुये लेकिन उसमें मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी उच्च विद्यालय हमारे क्षेत्र में हैं और बिहार में हैं, उसमें भवन की कमी है। पिछली सरकार ने प्रत्येक उच्च विद्यालय के लिये 26 लाख रूपये दिये थे जो किन्हीं कारणों से वहां के एच0एम0 ने या प्रबंध समिति ने उसे खर्च नहीं किया, आज पांच साल गुजर गये, एक संगठन का निर्माण विभाग ने किया उस संगठन के माध्यम से बनाने का काम किया लेकिन अभी तक उस दिशा में सही से काम नहीं हो पा रहा है । इसीलिये मैं कहना चाहूंगा कि जितने उच्च विद्यालय हैं, जिसमें 26 लाख रूपये वापस कर दिये गये, उसको उस संगठन के माध्यम से शीघ्र बनाया जाय ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और स्कूल में जो ऊर्दू बच्चे थे, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया थी, पिछले दो-तीन वर्षों से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है और इसको ले कर उर्दू बच्चों में उर्दू अविभावकों में एक आक्रोश है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी सारे व्यवधान को सारे अड़चनों को दूर करते हुये इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे । एक जो सरकार की मंशा थी कि प्राथमिक विद्यालय,माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय पंचायत में हो, सो हुआ । हमारे यहां जो बड़ी चुनौती थी कि बच्चे घरों से निकल कर स्कूल तक नहीं आते थे, इसमें एक बड़ी सफलता हुई कि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल में आ रहे हैं । परन्तु एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो सरकार के समझ में आया था कि हम नहीं दे पा रहे है, उसको दूर करने के लिये सरकार ने बड़ा कदम मिशन-गुणवत्ता नाम से एक संगठन बनाया है, उस दिशा में ताकि हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकें । मैं इतना जरूर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो आप देना चहते हैं मिशन गुणवत्ता के नाम से माननीय सदस्यों को भी जोड़ने का काम करें ताकि लोग समझ सकें कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस तरह गुणवत्ता बच्चों को देना चाहती है । हम चाहेंगे कि विभाग माननीय विधायकों को एक मीटिंग बुलाकर आपकी गुणवत्ता का क्या पैमाना होगा, क्या तरीका होगा ताकि माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जो विद्यालय हैं,उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और उस

दिशा में वे आपके भागीदार बन सकें । माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहूंगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करने के लिये माननीय विधायकों की एक मीटिंग विभाग बुलाये और किस तरह से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं उसमें आप माननीय विधायकों से सहयोग लें । हमलोग पूरी तरह सहयोग करेंगे । कुछ गंभीर बात है जिसकी ओर मैं सरकार का èयान आकृष्ट कराना चाहता हूं । विपक्ष यहां पर नहीं है तो हम्हीं लोग कुछ कमियों को रखना चाहेंगे । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 (1) के अन्तर्गत कोई भी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा से शैक्षणिक संस्था संस्थापित करेगा, संचालित करेगा और प्रशिक्षित करेगा । यह भारतीय संविधान में भी अधिकार है और यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में भी प्रावधान है । लेकिन भारत सरकार जिन विचारधाराओं की सरकार है, वह जो पूरे देश में कर रहा है लेकिन इस बिहार के सरजमीं पर मिथिला यूनिवर्सिटी ने भी आपके इस माईनॉरिटी इन्स्टीच्यूशन की स्वतंत्रता को भंग करते हुये वह अपने प्रबंध समिति और चयन समिति बनाने का आदेश वह अपने अनुकूल दिया है । इसीलिए हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री इस तरह के कार्यों को रोकने के लिये क्या आदेश देने जा रहे हैं, अपने उत्तर में जरूर देंगे, मैं इसकी अपेक्षा सरकार से करता हूं । साथ ही, मैं इतना जरूर कहूंगा कि केन्द्र सरकार जो बहुत ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की, उसको पूरा नहीं किया, स्पेशल पैकेज देन`की बात की लेकिन उसको पूरा नहीं किया, सवा लाख करोड़ देने की बात की लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया और जो अभी उसने बजट पेश किया है, इसमें 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का उसने प्रस्ताव बताया है, उसमें एक भी यूनिवर्सिटी बिहार को नहीं देने की बात कही गयी । यह बहुत निन्दा की, बात है । साथ ही माèयमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार को कोई तवज्जो नहीं दिया गया । सर्व शिक्षा का पैसा जो केन्द्र के पास बिहार का बकाया है, उसको भी देने का काम नहीं किया । मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जिस तरह अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को उच्च शिक्षा में प्रभावी तौर से रखना चाहती है और राज्य के प्रमुख पदों पर, यूनिवर्सिटी के प्रमुख पदों पर ला कर शिक्षा का भगवा करण करना चाहती है और यूनिवर्सिटी और कैम्पस के इन्वायरमेंट को खराब करना चाहती है, इसका उदाहरण है, ए0एम0यू0 का लगातार ऑब्जेक्शन चल रहा

है, जे0एन0यू0 पर लगातार उसका ऑब्जेक्शन चल रहा है, जामिया पर लगातार उसका ऑब्जेक्शन चल रहा है । अभी कन्हैया का देखिये, उसके साथियों का मामला देखिये । साथ ही अभी रीचा नाम की ईलाहाबाद में छात्र यूनियन की प्रेसीडेंट है,128 सालों के बाद उस यूनिवर्सिटी में कोई लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया । रोहित बेमूला के साथ किस तरह ए0बी0बी0पी0 भारतीय जनता पार्टी के छात्र संघ ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया । इस तरह की नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी मुखालफत हमलोग यहां पर करते हैं और जो राष्टªवाद के नाम पर एक नैरो डिफनेशन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है । देश में एकेडमिक इन्वायरमेंट को खराब करने का काम किया जा रहा है । उसकी भी हम निन्दा करते हैं । साथ ही हम यह जरूर बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्राथमिक और माèयमिक शिक्षा में बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है,उच्च शिक्षा में भी बेहत्तर विचार रखती है, जिस रफ्तार से महाविद्यालयों का,

क्रमश :

टर्न-16/सत्येन्द्र/9-3-16

श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन(क्रमश:):उच्च विद्यालयों के टीचरों का रिटायरमेंट हो रहा है उसमें लगातार सरकार के तरफ से यह आ रहा है कि टीचरों की बहाली लेंगे लेक्चरों की बहाली लेंगे लेकिन जून-जुलाई से नया सेशन शुरू होगा, जिस रफ्तार से बिहार की जनता को शिक्षा की तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जून-जुलाई तक सरकार निश्चित रूप से टीचरों की बहाली का काम करे और हम यह देखते हैं कि समस्तीपुर जैसा जगह जहां 30-40 लाख की आबादी हैं वहां केवल दो कॉलेजों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई होती है और हजारों बच्चे जो गेजुएट होते हैं वो पी0जी0 की पढ़ाई करने से बंचित हो जाते हैं चूंकि पी0जी0 के मान्यता उसको यूनिवर्सिटी नहीं दे

रहा है हम चाहेंगे कि शिक्षा विभाग इसका खुद मोनेटरिंग करे। महोदय, बिहार में बहुत सारे कॉलेजे होंगे जहां पी0जी0 की पढ़ाई के लिए बच्चे को जगह नहीं मिल पाता है और अब केन्द्र सरकार ने एक बाध्यता कर दी है कि किसी भी चाहे यू0जी0सी0 का पैसा हो या रूसा का पैसा हो उसको देने के लिए वो कहती है कि नैक कराना होगा तो मुझे लगता है कि नैक की अनिवार्यता के कारण बिहार विकास के पैसे से बंचित हो जायेगा। आज मुझे लगता है कि पूरे बिहार में 40-42 कॉलेज का ही नैक हो सका है तो जो अनिवार्यता है उसको कैसे दूर किया जायेगा क्योंकि बिहार के कॉलेजों में जो सीमित संसाधन है उसमें नैक कराना काफी कठिन है इसलिए इन कठिनाईयों को दूर किया जाय ताकि नैक का काम किया जा सके। महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के द्वारा लगातार अच्छा प्रयास किया गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मौका मिला और पांच प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि अगले साल से आ जायेंगे। आई0आई0एम0 बोध गया यूनिवर्सिटी में खोला गया है जिसमें इस साल से पढ़ाई शुरू हो जायेगा। अभी सरकार ने संकल्प लिया है जिसके तहत हमारे प्रत्येक जिला में पोलिटेकनिक कॉलेज खुल रहे हैं प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। लगभग जगहों पर वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने का प्रावधान है। एक हजार रू0 इसके लिए इन्होंने उपबंध भी कर दिया है इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज जो हमारे गरीब बच्चे हैं,जो छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गयी है ताकि वो उच्च शिक्षा ले सकें। इसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं साथ ही प्रत्येक जिला में जे0एन0एम0 स्कूल,ए0एन0एम0 स्कूल,पारा मेडिकल जैसी तमाम व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं तमाम सरकार के इन प्रयासों का समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन आशा और विश्वास के साथ बिहार की जनता से महागठबंधन को समर्थन किया था हम तमाम लोग मिलकर उस आशा पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मेवा लाल चौधरीः सभापति महोदय,माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅं। माननीय महोदय,अगर शिक्षा में विकास देखी जाय अपने बिहार में और तुलना अगर पूरे भारत वर्ष से की जाय तो शायद हम सबसे आगे हैं। हम ये वाक्या इसलिए कह रहे हैं महोदय कि भारत वर्ष घुमने का मुझे मौका मिला है और हम हर जगह पदस्थापित होकर काम किये हैं चाहे शिक्षा में विकास का मामला हो,चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो नये नये कॉलेज खोलने का हो, चाहे वो प्राईमरी स्कूल की बात करें, चाहे वो सेकेन्डरी स्कूल की बात करें,चाहे वो कॉलेज खोलने की बात करें, आज हमलोग सबसे अब्बल हैं, हमलोग सबसे आगे हैं। एक छोटी सी वाक्या है महोदय, हम शिक्षा विभाग का ही डेटा देख रहे थे। 9वीं क्लास के बाद जो हमारा प्रोसपोनेंट हैं,रेसियो है ब्याज और गर्ल का, लड़के और लड़कियों का उसका अनुपात बिल्कुल बराबर है और आज से पन्द्रह साल पहले से अगर इसकी तुलना की जाय तो पहले 80 लड़कों में एक लड़कियां स्कूल आया करती थीं और आज हम उस आयाम में पहुंच गये हैं कि आज दोनों का अनुपात बिल्कुल बराबर है। महोदय,इससे सोसाईटी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हमने इसका डिटेल एनलाईसिस किया था महोदय,इससे जो हमारा पोपुलेशन ग्रोथ हुआ है जो जनसंख्या में वृद्धि है वह बिल्कुल कम हो गया है। दस साल पहले से इसकी तुलना करें तो पहले जहां जनसंख्या की वृद्धि हमारी 2.5 प्रतिशत थी वहां आज हमलोग 2.1 प्रतिशत पर आ गये हैं। महोदय,इसका सीधा असर शिक्षा से है, इसका सीधा ताल्लुकात शिक्षा से है। चाहे वो लड़कियों की शिक्षा हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, महोदय जो आंकड़ा हमारे पास है शिक्षा विभाग का, आज हमारी बिहार की जनसंख्या तकरीबन 11करोड़ है और 11 करोड़ में से 2 करोड़ बच्चे इंभोल्वड हैं पढ़ने के लिए। प्राईमरी शिक्षा से लेकर के कॉलेज शिक्षा तक यह बहुत बड़ा द्योतक है कि हमलोग शिक्षा में कितना आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग आगे हर तरह से बढ़ रहे हैं महोदय,चाहे अपने राज्य में फिलोसिप की बात करें, चाहे हम छात्रवृत्ति की बात करें, चाहे हम न्यू इंस्टीच्यूशन की बात करें। आज

माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में जरूर कहेंगे कि हर जिला में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोल रहे है उनका प्रस्ताव है पोलिटेकनिक कॉलेज खोलेंगे, आई0आई0टी0 खोलेंगे और सबसे बड़ी बात है जो नई शिक्षा नीति आयी है महोदय उसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोविजन है, एक बहुत बड़ा कदम हैं शिक्षा में बिहार को आगे ले जाने का और मुझे उम्मीद है जब प्राइवेट इंस्टीच्यूशंस आयेंगे तो वहां हमारे बिहार के बच्चे ही पढ़ेंगे और उनमें कम्पटीशन की भावना आयेगी और इस भावना से हमारे शिक्षा में दिन व दिन बढ़ोत्तरी होगी और दिन ब दिन हमलोग आगे बढ़ते रहेंगे। महोदय,इसके वाबजूद भी हमारा एक दो सुझाव है आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से, अगर हम प्राईमरी स्कूल की बात करें महोदय, जरूरत है आज बच्चों में इंटरेस्ट क्रियेट करने का। बच्चों में जबतक इंटरेस्ट क्रियेट नहीं होगा, बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं। मèयाह्न भोजन के समय वो खाना खाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आज बच्चे में इंटरेस्ट क्रियेट हो जाय तो बच्चे खुद ब खुद स्कूल में रहना पसंद करेंगे और जब बच्चे स्कूल में रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए मेरा एक ही सुझाव है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि सर,आज की पढ़ाई जो मॉडर्न पढ़ाई की बात करते हैं जिस स्मार्ट क्लास की बात करते हैं ये कुछ नहीं है। एक भिजुअल एड् के माèयम से उनकी क्रियेटिभिटी को जगाने की बात है न कि फोर्स करने की बात है। माननीय शिक्षा मंत्री जी,मुझे मौका मिला था ब्रिटिश एजुकेशन के अध्ययन करने का और अमेरिकन एजुकेशन के अध्ययन करने का। अमेरिका में जो शिक्षा होती है वह नन फार्मल शिक्षा होती है। आठवें क्लास तक वहां कोई कोर्स नहीं होता है,कोई एकेडमिक कलेंडर नहीं होता है लेकिन ब्रिटिश चूंकि वह हमसे मिलता जुलता है वहां पर एकेडमिक कलेंडर होती है इसलिए महोदय मेरा जो अपना अनुभव है अगर बच्चों को 5वीं क्लास तक 6ठी क्लास तक ननफार्मल एजुकेशन दिया जाय, उन्हें कोई एकेडिमिक बर्डेन नहीं दिया जाय तो आप बच्चे को देखेंगे तो पायेंगे कि बच्चे के वजन से ज्यादा उसके बस्ता का वजन हो जाता है । उससे कभी कभी बच्चे का मेंटर

ग्रोथ नहीं होता है। अगर उसमें इस तरह का अवेयरनेस क्रियेट किया जाय इंटरेस्ट किग्रेट किया जाय पिक्चर के माध्यम से, ऑडोभिजुअल के माध्यम से तो शायद हमारे बच्चे ज्यादा रहना पसंद करेंगे स्कूल में, बजाय बच्चे स्कूल में आते हैं खाने के वक्त और खाना खाकर वो चले जाते हैं उससे ज्यादा हमको फायदा होगा । दूसरा मेरा सुझाव है बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही आज हमारे यहां प्राइवेट संस्था बहुत आ रही है प्राईवेट संस्था को हमलोग कभी नहीं देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वहां पर पैरेंटस टीचर मीटिंग, टीचर स्टूडेंट का संबंध, रिलेशनशीप बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जितने भी पैरेंटस है वो सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी पढ़ाई की नहीं है हम सोशल रिस्पौंसब्लिटी से भाग रहे हैं हम अपनी जिम्मेवारी से समाज से भाग रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल में चले गये तो पैरेंटस ये सोचते हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार हमारे बच्चे को पढाये लेकिन सर, जबतक हमलोग सोशल एवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं करेंगे। ये जिम्मेवारी हमारी टीचर की होनी चाहिए कि हम पैरेंटस को अवेयर करें। हम उन्हें बतलायें कि शिक्षा का क्या महत्व है हमारे सोसाईटी में, शायद अगर पैरेंटस में अवेयरनेस आयेगी तो हमें ऐसा लगता है पैरेंटस भी ये सोचेगा कि हमारे बच्चे पढ़े। अभी सर, चूंकि हमलोग गांव देहात से आते हैं वो बहुत ज्यादा पैरेंटस पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है उनके बच्चे स्कूल जाते हैं बस वो अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है? महोदय स्कूल से पहले बच्चों की शिक्षा उनके घर से शुरू होती है अगर हमारे घर में शिक्षा ठीक हो जाय तो शायद हम स्कूल के शिक्षा में ज्यादा आगे बढ़ जायेंगे। महोदय, हम आपके माध्यम से अपने शिक्षा मंत्री जी को एक और सुझाव देना चाहेंगे। आज हम क्वालिटी टीचर की बात करते है,गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं। शायद हम भूल गये हैं कि आज हमारे पास गुणवत्ता वाले टीचर नहीं है। अगर गुणवत्ता टीचर होते तो गुणवत्ता टीचिंग करा लेते। हमारा अपना सुझाव है सर,जबतक टीचर को यह आवश्यक नहीं बना दिया जाय कि आपको 6 महीने का जरूर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है और यह उनको कम्पलसरी कर दिया

जाय तो शायद टीचर जाना नहीं चाहेंगे। जो टीचर पंचायत से बहाल हुए हैं वो टीचर उसी गांव के लोग है, उसी जिला के लोग है और जिसके कारण वह जिला छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। मेरा तो यह भी सुझाव रहेगा महोदय आपके माध्यम से अगर उनको अन्तरजिला स्थानांतरण करने का शिक्षा मंत्री विचार रखते हैं तो शायद उनमें थोड़ी बहुत सिंसियरिटी जरूर पढ़ाई में आयेगी, बजह वह घर में रहकर जो पढ़ा रहे हैं। महोदय, हम अगर कॉलेज शिक्षा की बात करें महोदय,एक दो मिनट और लेंगे। आज कॉलेज में बहुत सारे लोग हमारे सदस्यगण हैं और बहुत बड़ा सवाल उठाया है। हम अपने शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि सर, जो पुराना सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम था पढ़ाई का उसकी जगह सेमेस्टर सिस्टम में आने का अगर शिक्षा मंत्री जी उस पर विचार करते हैं तो शायद कॉलेज का जो लेवेल घट गया है वह लेवेल आ जायेगा।

टर्न–17/मधुप/09.03.16

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : एक मिनट सर । शिक्षा मंत्री जी, हम अपने क्षेत्र के बारे में कुछ आपको अवगत कराना चाहेंगे । हमारे तारापुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी बी0एड0 कॉलेज नहीं है, बच्चे और बच्चियॉं वहॉं से पढ़ने के लिए 40 कि0मी0 या तो भागलपुर जा रहे हैं या मुँगेर जा रहे हैं । बहुत असुविधा होती है । बड़ी कृपा होगी, अगर आप इसके ऊपर विचार करें । महोदय, पेपर में आपका एक वक्तव्य आया था कि हम बहुत सारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज.....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : एक मिनट । बहुत सारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाना चाहते हैं । तारापुर का एक कॉलेज है जो 1947 में इस्टैबलिश हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से वह आगे नहीं बढ़ पाया है । महोदय, अगर आर0एस0 कॉलेज, तारापुर को मॉडल कॉलेज बनाने के लिए सोचें तो बहुत बड़ा आपकी कृपा होगी । दूसरा, तारापुर में एक गर्ल्स हाई स्कूल चाहिये । हर प्रखंड में है लेकिन तारापुर में गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है । आपसे निवेदन करेंगे कि इसपर ध्यान दिया जाय ।

श्रीमती समता देवी : महोदय, मैं समता देवी, बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र की सदस्य हूँ । मैं सरकार के पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूँ । सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान शिक्षा पर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि किसी महापुरूष ने कहा है कि शिक्षा वह औजार है, जिससे सम्पूर्ण संसार को बदल सकते हैं । शिक्षा के बिना मानव का जीवन अंधकार में है ।

खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा पर मैं कहना चाहती हूँ कि पुरूष किसी न किसी प्रकार से शिक्षा के औसत ऑकड़े में महिलाओं से आगे है । लेकिन महिला जो समाज रूपी वाहन की महत्वपूर्ण पहिया है, उनकी शिक्षा पर कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है । ऐसा माना जाता है कि एक महिला को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है । शिक्षा को किसी सीमित अर्थ में नहीं रखा जाय, केवल नौकरी पाना शिक्षा का अच्छा प्रभार ग्रहण करने का पैमाना नहीं हो सकता । जैसे उदाहरण के लिए यदि आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी को आपकी मदद चाहिए और आप उस व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं तो आपकी शिक्षा अधूरी है । भले ही आप शिक्षा के आंकड़ेबाजी के गणित में सफल हो जायं लेकिन जीवन के आंकड़ेबाजी में सफल नहीं हो सकते हैं ।

हमारे देश और हमारे राज्य को आज ऐसी ही शिक्षा की जरूरत है जो आर्थिक दृष्टि से तो सहायक हो ही, साथ ही साथ नैतिक उत्थान भी करे । हमारी सरकार ने हमारे राज्य को बदलने के लिए कई अहम कदम उठाया है । शिक्षा को समाज से पूर्णतः जोड़ने के लिए प्रयास किये गये हैं । खासकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बाराचट्टी के संबंध में सभापति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी-पठारी एवं जंगलों से घिरा है और उग्रवाद प्रभावित इलाका है, वहाँ शिक्षा का घोर अभाव है । इसमें महादलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर लोग निवास करत हैं । वहाँ के लोगों का शिक्षा से दूरी होने का मुख्य कारण है कि अभी तक न तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज है, न ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है, न ही छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉलेज या छात्रावास ही हैं । जिसके कारण से वहाँ के लोग शिक्षा से कोसो दूर हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी स्कूल एवं छात्रावास हमारे क्षेत्र में हैं उनकी हालत काफी जर्जर है, जिसके कारण सही तरीके से पठन-पाठन का कार्य नहीं हो पाता है, वहाँ शिक्षा की काफी कमी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महादलित छात्रावास है, भवन काफी जर्जर है । उदाहरण के लिए अम्बेडकर अनुसूचित विद्यालय मनफर, मटिहानी एवं बोगला को देखा जा सकता है और उचित कार्रवाई करने की माँग करती हूँ । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की शिक्षा संबंधी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ ।

सभापति महोदय, हमारे विधान सभा बाराचट्टी में केन्द्र द्वारा सैनिकों के लिए फायरिंग रेंज है जो गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत बुमेर के ग्राम बिघी और ग्राम गोही में यह अवस्थित है । जिसमें 14 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और 50 से अधिक जानवरों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन आज तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, जो

खेद का विषय है। मैं माँग करती हूँ कि जिनकी जान-माल गयी है, उन्हें क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए ।

महोदय, मैं शराबबंदी का समर्थन करती हूँ लेकिन जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित कर पेपर में कहा गया है कि 5 किलोग्राम महुआ रख सकते हैं । जबकि मेरे विधान सभा बाराचट्टी में बहुत से किसान के खेत में महुआ का पेड़ है जिसमें 01 क्विंटल से अधिक का ऊपज होता है । इस परिस्थिति में किसान क्या करें, मैं सरकार से राय जानना चाहती हूँ ।

बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी, पठारी एवं जंगल से घिरा है, वहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । जबकि सरकार द्वारा निहित है कि जिस गाँव में 50 प्रतिशत् से अधिक आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है तो उसे आदर्श गाँव के रूप में चयनित किया जाय । इसलिए मैं माँग करती हूँ कि 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे क्षेत्र में बहुत से गाँव जहाँ इनकी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है, उन्हें आदर्श गाँव में जोड़ा जाय ।

बी0पी0एल0 परिवार में सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र बाराचट्टी में किस हॉस्पीटल में इसके माध्यम से ईलाज होगा, उसका नामकरण नहीं किया है, जो दुखद है । इसमें कार्रवाई करके तत्काल लागू कराया जाय ।

स्वच्छता - बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र में अभी तक बहुत कम संख्या में शौचालय का निर्माण कराया गया है, जो न के बराबर है । मैं माँग करती हूँ कि बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी घरों में शौचालय बनाया जाय।

पेयजल की आपूर्ति - बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र में पेय जलापूर्ति का कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है लेकिन अभी भी कार्य बाधित है । उसे

अविलम्ब चालू कराने का आदेश दिया जाय ताकि गरीब परिवार के लोगों को पेयजल मुहैया हो सके ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग शिक्षा पर बोल चुके हैं, जबतक शिक्षा समान ढ़ंग से नहीं मिलेगा तबतक गरीब-गुरबा को शिक्षा और नौकरी में भागीदारी नहीं मिल सकता है । हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिये, पढ़ाई एक जैसा होना चाहिये चाहे नेता के बच्चा हों या अफसर के बच्चा हो । एक समान पढ़ाई व्यवस्था जबतक नहीं होगी, तबतक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । कंपिटीशन का जमाना है, टेक्निकल शिक्षा का जमाना है, गरीब-गुरबा के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें । इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ । जय हिन्द, जय बिहार ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा और सरकार के पक्ष में एक आदिवासी महिला विधायक को बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ । साथ ही साथ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का भी आभार प्रकट करती हूँ । साथ ही माननीय अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब का भी आभार प्रकट करती हैं, आभार प्रकट करती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी का, चूँकि इन्होंने पहली बार पूरे बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा की पहल की है ।

महोदय, आपके माध्यम से सदन को मैं बताना चाहती हूँ कि महागठबंधन को अपार बहुमत मिला । बहुमत मिलने का कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास का नारा बुलंद किया है ।

...क्रमशः....

टर्न-18/अंजनी/दि0 9.3.16

....क्रमशः...

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : साथ-ही-साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा, अकलियतों के मान और सम्मान को बिहार ही नहीं अपितु देश में मजबूत करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी एवं आर्थिक हल एवं युवाओं को बल दिलाने वाले आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और साथ-ही-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय का नारा ही बिहारियों का विश्वास और आर्शीवाद का ही देन है । इस निश्चय में शिक्षा पर बहुत ही प्रमुख बल दिया गया है । जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल देना, शिक्षित बिहार बनाना, ज्ञानवान बिहार बनाना, छात्र-छात्राओं को शिक्षा पर समान रूप से ध्यान देना, नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, जिसका कि उदाहरण है 35 प्रतिशत के साथ-साथ सभी रूप में महत्व देना तथा शिक्षा को रोजगार से जोड़ना आदि हैं । सोना-चांदी और दौलत लूटा जा सकता है लेकिन ज्ञान लूटा नहीं जाता, ज्ञान बाँटा जाता है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

जिस तरह देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नारा था- करो या मरो, ठीक उसी तरह से बिहार में शिक्षा का अलख जगाने के लिए आदरणीय लालू जी का नारा था- जन्म दिया तो शिक्षा दो और पढ़ो या मरो । माननीय नीतीश जी, लालू जी, युवा नेता तेजस्वी जी का संकल्प है कि बिहार को ज्ञानवान बनायेंगे, शिक्षा घर-घर पहुंचायेंगे । गरीब, शोषित-पीड़ित आदिवासी, अकलियत, अतिपिछड़ा को अधिक बल देंगे । हमारी सरकार का यह निश्चय है कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा दी जायेगी । हर पंचायत में एक-एक हाई स्कूल खोले जायेंगे। सारे पदाधिकारी एवं अधिकारी को हमारी सरकार ने निर्देशित किया है कि बेहतर शिक्षा देना सुनिश्चित कराया जाए और कदाचार मुक्त बिहार बनाना, छात्रवृत्ति,

पोशाक, साईकिल बांटने का संकल्प लिया है । महोदय, सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतर प्रबंध किया गया है ।

माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सात निश्चय का संकल्प है कि श्रम संसाधन विभाग से युवा-युवतियों को स्पोकेन इंग्लिश, स्कील प्रशिक्षण, कम्प्यूटरकृत कौशल विकास । प्रत्येक जिला में महिला आई0टी0आई एवं प्रत्येक अनुमंडल में आई0टी0आई0 खोलने का निर्णय लिया गया है । बिहार के युवक, युवतियों को शिक्षा ऋण दिलाना, जिससे उनको रोजगार मिल सके और बेरोजगारी दूर हो, तभी बिहार का सम्बल और बिहार का मान-सम्मान समृद्ध होगा । बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो । गरीबों के घर में ज्ञान का दीप जलेगा । भगवान बुद्ध ने कहा था- बुद्धम शरणम् गच्छामि, यानि बुद्ध के शरण में जाओ । दुनिया में ज्ञान और शिक्षा ही दौलत है । बिहार में मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में नालन्दा विश्वविद्यालय है, जो दुनिया में ज्ञान के मंदिर के रूप में जाना जाता है । हमारे कमिश्नरी भागलपुर में विक्रमशिला है, जो बिहार में ही नहीं बल्कि देश-दुनिया में शिक्षा का द्वीप कहा जाता है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि बिहार तभी समृद्ध बनेगा जब हम सभी लड़के-लड़कियों को शौचालय की सुविधा देंगे । भाजपा सरकार अब द्रोणाचार्य बनकर एकलव्य का अंगूठा नहीं काट सकता है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के महिला अध्यक्ष को भी तंग और अपमानित करने का काम आर0एस0एस0 और भाजपा के द्वारा किया गया । साथ-ही-साथ रोहित बेमुल्ला जैसे लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया । अध्यक्ष महोदय, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जे0एन0यू0 है । वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष, जो बिहार का बेटा है उसे भी अपमानित कर एवं आतंकवादी कहकर जेल भेजने का काम किया गया। भाजपा की दोहरी नीति और असली चेहरा यही है, जो देश को कलंकित करते हुए देश में भाईचारा खत्म करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है । ऐसे जुमलेबाज सरकार को हमारी सरकार और भारत के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगी या उनसे मैं आग्रह करूँगी कि पूरे बिहार में शिक्षा की अलख जगी है । शिक्षा अलख जगने के साथ-साथ हम इनसे यह भी आग्रह करने के लिए तत्पर हैं कि आज की जो शिक्षा है, उसमें 40 पर 1 शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, वह अभी तक पूरे बिहार में फुलफील नहीं हो पाया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी आग्रह करूँगी कि इसी साल या अगले साल तक 40 पर 1 शिक्षक की नियुक्ति हो जानी चाहिए ताकि जो शिक्षा की नीति है, वह आगे बढ़ते जाय । महोदय, मैं एक और बात आग्रह करना चाहूंगी कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूँ, वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, अकलियत बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर शिक्षा की स्थिति पहले से बेहतर है । मैं एक और बात की ओर शिक्षामंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि जो स्कूल का समय-सीमा है वह 9.00 बजे से 4.00 बजे तक । 9.00 से 3.00 बच्चे रहते हैं और 3.00 से 4.00 बजे तक जो कमजोर बच्चों का समय रखा गया है, उसके लिए आप जरूर मोनेटरिंग करेंगे ताकि कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जा सके । इसके साथ-ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम, आप कृपा दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री महबूब आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, दो मिनट में सब कुछ नहीं बोला जा सकता है । फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जो बजट पेश है, इस बजट के जरिए जो गरीबों का पैसा लिया जाता है, उससे वह शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है गरीब के बच्चों को । आज जिस तरह से केन्द्रीय सरकार शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण करने के लिए उतारू है और आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे जे0एन0यू0 जैसे बड़े आंदोलन में उतर गये । महोदय, गांव की हालत यह है कि जो शिक्षा दी जा रही है, वह गुणवत्ताविहीन शिक्षा दी जा रही है । उसमें एक बात है

कि बड़े लोग, दौलत वाले लोग के बाल-बच्चे कॉनवेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं । इस तरह से आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में नाम रहेगा लेकिन अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं तो आपको कानवेंट स्कूल में पढ़ना होगा । तो यह हालात हैं महोदय और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का अभाव है तो लगातार 40 साल से भी ज्यादा समय से जो वित्त रहित महाविद्यालय के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है तो उनका सरकारीकरण क्यों नहीं किया जाता ? अगर सरकारीकरण करने का आपका मन नहीं है तो उन शिक्षकों को प्लस-2 में नियुक्त क्यों नहीं कर देते ? महोदय, आप जो माइनोरेटी इन्स्टीच्यूसन खोलने के तहत जो आर्टिकल-29 और 30 के अंतर्गत जो अधिकार हैं, उसमें सरलता लायी जानी चाहिए। माइनोरिटी द्वारा संचालित जो वर्षों से मदरसा शिक्षा दी जाती है, आपकी भी बात करते हैं, गणित और अंग्रेजी की जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो मदरसों का सरकारीकरण किया जाय। महोदय, मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ायी जाय । जिस तरह से हवा, पानी, सूर्य की रोशनी जनता को उपलब्ध होनी चाहिए, उपलब्ध है, प्रकृति ने उपलब्ध करा दिया है.....

अध्यक्ष : लाल बत्ती जल चुकी ।

श्री महबूब आलम : ठीक है महोदय लाल बत्ती जलती है तो लाल झंडे के वारिस हैं हमलोग, तो यह भी बात है । तो शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया जाय, वरन् इनडायरेक्ट रूप में, यह सरकार कभी जे0एन0यू0 और रोहित बेमुल्ला की बात कर रही थी, तो रोहित बेमुल्ला की बात करने के लिए आज बाèय हो गयी है पूरे हिन्दुस्तान की प्रगतिशील जनता.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद । डॉ0 रामानुज प्रसाद जी, आपको पांच ही मिनट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद सरकार का उत्तर होगा पांच मिनट में । आप पांच मिनट में ही अपनी मूल बात, सार बात कह डालिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हमारे माननीय सदस्यों ने धन्यवाद दिया है ।

क्रमशः

टर्न–19/शंभु/09.03.16

डा0 रामानुज प्रसाद : क्रमशः....मैं भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि बिहार का जो शिक्षा का चित्र देश और दुनिया के मानचित्र पर खींचा हुआ था, उसपर इन्होंने कुछ ब्रश मारने का काम किया है, प्रयास किया है ब्रश मारने का– निजी अखबार हो, निजी मीडिया हो, मैं परसों भी पढ़ रहा था एक अखबार में उसने बताया था कि पहले चिट फेस होता था बिहार में उसको हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने उस धूमिल छवि को सुधारने का प्रयास किया है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की जो उपलब्धि है या इस बार का जो बजट में प्रोविजन है। आज की मांग जो रखी गयी है माननीय मंत्री के द्वारा मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जो स्थिति है बिहार में शिक्षा की निश्चित तौर पर सरकार प्रयासरत है, लेकिन और प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षा में प्रयास करने की जरूरत है, चूंकि आज भी जो हमारे विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक हैं वे पढ़ाई के काम छोड़कर के दूसरे और सारे कार्य करते हैं। जो शैक्षणिक कार्य है उसको छोड़कर के गैर शैक्षणिक कार्य में या तो हमारा सिस्टम उसको लगाये हुए है, हमलोग जब क्षेत्र में घूमते हैं और देखते हैं सरकारी विद्यालयों के जो हालात हैं और जिस तरह से दुनिया में शिक्षा की और नॉलेज की बात हो रही है– नॉलेज में हम सफर कर रहे हैं और इस एरा में गरीब के बच्चे क्या वे खिचड़ी खाने के लिए स्कूलों में जाते हैं ?

क्या हमारे विद्यालय इसी हालात में चलेंगे और हम एक बेहतर, सुंदर बिहार बनायेंगे ? हमारी सरकार का अगर संकल्प है कि सुंदर और मजबूत बिहार बनाना है, देश में अपने को भी अव्वल राज्य के रूप में प्रतिष्ठापित करना है तो कोई भी राज्य राष्ट्र तब तक नहीं अपने देश में या दुनिया में नाम कमा सकता है जब तक उसके नागरिक, उसकी महिलाएं पढ़ी लिखी और वाजिब शिक्षा रेगुलर एजुकेशन और रियल एजुकेशन जब तक नहीं लेते हैं, तब तक हम समझते हैं कि उपलब्धि नहीं मिलनेवाला है। जहां तक हमारी सरकार जो आयी है अपार बहुमत से जीतकर तो माननीय नीतीश कुमार जी का मिशन और लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय और कांग्रेस पार्टी की जो अवधारणा है, तीनों का जो सम्मिलित प्रयास है देश को बनाने का जो सपना है, उस सपना पर विश्वास करके जनता ने हमको यह बहुमत दिया है। हम चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय जो हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी की अवधारणा है उसको अगर मजबूत करना चाहते हैं और विकास का जो मिशन है माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को निश्चित तौर पर शिक्षा में जो प्रयास इनका हुआ है उसको और बेहतर करने की जरूरत है। चूंकि सामाजिक न्याय बगैर शिक्षा के नहीं आ सकता। स्कूल के माध्यम से ही, शिक्षा के मध्यम से ही गरीबों में आत्मबल पैदा होता है। कोई भी गरीब का बच्चा अगर पढ़लिख लेता है, गरीब का बेटा भी डाक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनकर के अपने संबंधित कार्यालयों में बैठता है तो निश्चित तौर पर उसको आत्म सम्मान मिलता है, सामाजिक सम्मान मिलता है और सामाजिक न्याय परिलक्षित होता है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल सुधारे जाएं और उसमें शिक्षा मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास हो रहा है।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

डा0 रामानुज प्रसाद : हमारी सरकार ने रोड मैप बनाया है बहुत सी चीजों की, लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षा का एक रोड मैप हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय

शिक्षा मंत्री जी शिक्षा का एक रोड मैप हो उसमें सभी संबंधित विभाग जुड़े हों और सभी विभागों की मोनेटरिंग और मीटिंग सरकार ले और तब जाकर शिक्षा में जो भी आवश्यक तत्व है उसकी पूर्ति के लिए सफल प्रयास हो। मैं अपने क्षेत्र के एक मामले को उठाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, अभी अकीलपुर का इलाका है हमारा दानापुर के नीचे और हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां अगलगी में मैं गया था और अगल बगल के टोलों से भी एक कागज का टुकड़ा खोज रहा था पीड़ित परिवारों की सूची बनाने के लिए। वहां विद्यालय नहीं है, एक विद्यालय है तो वह जर्जर स्थिति में है। वह सुधरे, वहां उच्चतर विद्यालय, उच्च विद्यालय खुले इसके लिए मैं मांग माननीय शिक्षा मंत्री जी से करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, एक शब्द कहना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष : शब्द कि वाक्य ?

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, ये जो रसोइया है उसको 1250 रू0 मिलता है। मैं आग्रह करूँगा उसको 5 हजार कर दिया जाय। इसपर निश्चित रूप से घ्यान दिया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री अशोक चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी- फराज फातमी साहब, अभय जी, एज्या यादव जी, राजकिशोर सिंह, अजीत शर्मा, वशिष्ठ सिंह, अफाक आलम, शाहीन साहब सभी सदस्यों ने करीब 14-15 सदस्यों ने अपनी बात रखी। शिक्षा निश्चित रूप से एक नये बिहार के निर्माण में, 21वीं सदी के बिहार के निर्माण में एक बड़ा विभाग है। बाकी विभाग पथ

निर्माण हो, ऊर्जा हो, बाकी जो विभाग हैं वह डी0पी0आर0 बनाते हैं और योजना बनाते हैं, लेकिन शिक्षा ऐसा विभाग है जो बिहार के विकास का, बिहार का निर्माण करेगा, नये बिहार के निर्माण में अपना योगदान करेगा। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विभाग है और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से सजगता के साथ अपनी बातों को रखा है उन बातों को मैंने सुना है। निश्चित रूप से जो संभव हो पायेगा उसको हम इनकॉरपोरेट करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य की शुरूआत गांधी जी के इस पंक्ति से करना चाहता हूँ कि यदि इस दुनिया में सच्ची शांति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमें बच्चों को शिक्षा देने की शुरूआत करनी चाहिए। हम आभार व्यक्त करते हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिन्होंने पिछले वर्ष में जो सरकारें थीं उसमें बिहार में मूलभूत संरचनाओं के, शिक्षा में मूलभूत संरचनाओं का उन्होंने विकास किया। आज से अगर पांच साल, दस साल पूर्व जायेंगे तो देखेंगे कि इस प्रदेश में न शिक्षक थे, न शिक्षा का भवन था, लेकिन पांच दस वर्षों में इस सरकार ने शिक्षा के भवनों का निर्माण किया। साथ ही नियोजित शिक्षकों का भी इस प्रदेश में नियोजन किया है तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति एक नेतृत्वकर्ता जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और हम वैसे टीम के सदस्य हैं जिसके कैप्टन के पास विजन है, जो कैप्टन चाहता है उसमें दूरदर्शिता है। जो कैप्टन चाहता है कि हमारा बिहार हम वैसे बिहार बने जिससे दूसरे राज्य बिहार से अपने आप को कंपेयर करे। हम दूसरे केरल और गुजरात से नहीं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकें, दूसरे गुजरात और केरल जैसा राज्य बिहार से अपने को कंपेयर करे, वैसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन है। मानव बल को सुसज्जित, कौशल संपन्न और सशक्त बनाकर हम अपनी बड़ी जनसंख्या को वरदान में बदल सकते हैं। इसी उद्देश्य को घ्यान में रखकर हमारी सरकार शिक्षा में सर्वाधिक निवेश कर रही है। हम गर्व करते हैं कि बिहार वैसे राज्यों में है जो शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करनेवाला राज्य

है। बिहार सरकार के बजट का 15.13 प्रतिशत हम शिक्षा पर व्यय करनेवाले राज्य हैं ताकि बिहार के लोग अपने परिश्रम, बुद्धि और कौशल के आधार पर बिहार में राज्य के बाहर देश और दुनिया में अपने को प्रतिष्ठित करे। परिणामतः बिहार चतुर्दिक विकास और संपन्नता को प्राप्त करे। नवम्बर, 2015 में नयी सरकार बनने के बाद हमने प्राथमिकता के तौर पर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निश्चित उपाय किये। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड- बिहार के विकास पुरूष, जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के सपने को धरातल पर उतारने को ये सात निशचित लागू किया। इसमें पहला निश्चय है- आर्थिक हल, युवाओं को बल। इस निश्चय को लागू करने का जिम्मा शिक्षा विभाग ने लिया है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के कई मेधावी छात्र छात्राएं साधन की कमी के कारण आगे उच्च शिक्षा योग्यता रहने के बावजूद नहीं ले पाते हैं। हर नौजवान के आंखो में जीवन में आगे बढ़ने का एक सपना होता है। जिन परिवरों के पास और कोई धन संपत्ति नहीं होती है उनके पास समाज में अपनी स्थिति बेहतर करने का एक मात्र रास्ता उच्च शिक्षा ही होता है। हमारी सरकार उन नौजवान सपनों को पंख देना चाहती है। हमारे राज्य का कोई नवयुवक या नवयुवती आर्थिक तंगी के कारण अब पढ़ाई करने से वंचित नहीं रह पायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस निश्चय कार्य को करनी में बदलने के लिए बिहार राज्य के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रील, 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लागू हो रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराने का हमारा कार्यक्रम है। गांव, देहात में रहनेवाले गरीब गुरबा की बेटी बेटे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे मेधा शक्ति और श्रम शक्ति से संपन्न होने के बावजूद अर्थाभाव में उच्च शिक्षा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे विद्यार्थियों को अपने सपने को साकार करने का अवसर मिलेगा। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। इस प्रकार हमारा

पहला निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल- 1 अप्रील 2016 से लागू होगा। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में सुधार- हमारी सरकार ने पिछली बार जो मैट्रिक में कदाचार हुए और जिसके चलते प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बिहार की छवि धूमिल हुई। शिक्षा मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि कदाचार को रोकना है, बिहार की छवि को बदलना है। हम विकास करनेवाले सबसे बड़े राज्यों में हैं, हम इस देश में सबसे तेज गति से विकास करनेवाले राज्य हैं और इस तरह के कदाचार होने से बिहार में देश की और दुनिया में छवि खराब होती है। हमारी सरकार कृतसंकल्प है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा पूरी स्वच्छता के साथ हो, कदाचार की कोई संभावना नहीं हो, इंटर की परीक्षा में यह हमने पूरा करके दिखाया है। बिहार और भारत में ही नहीं देश और दुनिया में इसकी चर्चा है। दिनांक 28.02.2016 को दुबई में प्रकाशित गल्फ न्यूज दैनिक समाचार पत्र में कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था की हमारी सराहना छपी है। अररिया के एक शिक्षक से प्राप्त संवाद को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ :

Education is beautification of the inner world and outer world. I can't believe on my eyes When I see the current ongoing 12th exam's fairness. It has been a long time as being a teacher I never seen such a fair examination system. I am filled with the Joy. Hoping this will change the future of Bihar. Thanks to Nitish Government, his dedicated team of bureaucrats, teachers and all other members of examination reform system. (Bachchan from Araria). क्रमशः।

श्री अशोक चौधरी : ... क्रमशः ... कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए हमने निम्नलिखित व्यवस्था की । पूर्व वर्ष के परीक्षा में जिन केन्द्रों में कदचार के मामले सामने आये थे, उन केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई, जिन केन्द्रों के संबंध में गत तीन वर्षो में कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वहां केन्द्र नहीं बनाया गया । ऐसे महाविद्यालय एवं विद्यालय जहां कदाचार किये जाने की सम्भवानायें थीं, वहां यथासम्भव परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया । साथ ही जहां परीक्षा केन्द्र बनाया गया वहां पूर्व में तीन वर्ष केन्द्राधीक्षक रहे उनको भी इस बार केन्द्राधीक्षक नहीं बनाया गया ।

परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थी की संख्या के आधार पर दो से तीन सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये साथ ही परीक्षा केन्द्र की विडियोग्राफी की व्यवस्था भी पूर्व की तरह कराया गया । परीक्षा केन्द्रों पर समुचित विधि व्यवस्था के लिए बिहार पुलिस के जवान तैनात किये गये । साथ ही आवश्कतानुसार बिहार पुलिस एवं गृह रक्षा वहिनी के जवानों को संयुक्त रूप से तैनान किये गये ।

परीक्षा के पूर्व नियुक्त विक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित कर विक्षण कार्य की ट्रेनिंग दी गई ।

विक्षकों की प्रतिनियुक्ति रेन्डमनाईजेशन के आधार पर किया गया । राज्य के सभी 38 जिलों के लिए नॉडेल पदाधिकारी के रूप में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को परीक्षा कार्य के अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया ।

कदाचार अपनाये जाने के कारण, निष्कासित परीक्षार्थियों को उनके दोष के आधार पर एक से अधिक वर्षो के लिए निष्कासित किये जाने की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई ।

बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 को शक्ति से लागू किया गया ।

मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के स्तर से भी अनुश्रवण किया गया ।

निश्चित रूप से प्रयास किया कि इन्टर की परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में किसी तरह का कदाचार नहीं कराया जायेगा और हम उसमें सफल हुये हैं ।

हम धन्यवाद देते हैं शिक्षा विभाग के हमारे जो शिक्षकगण हैं, जो अभिभवकगण हैं और पूरी की पूरी शिक्षा विभाग की टीम को कि जो कहीं न कहीं हमारे ऊपर जो धब्बा लगा था, जो दाग लगा था उसको हमने धोने का काम किया है । हम केवल कदाचार मुक्त परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, पठन-पाठन को दुरूस्त करने का सीखने की प्रक्रिया को गहराई और विस्तार देने का काम साथ साथ किया है ।

इस वर्ष सेंट-अप परीक्षा के बाद सभी माध्यमिक विद्यालयों को खोलकर परीक्षा की दृष्टि से अभ्यास कराने का काम किया गय है । बिहार बोर्ड के द्वारा मोडेल पेपर, प्रकाशित किया गया ।

बच्चों के लिए प्रेरणा नामक अभ्यास सामग्री विभागीय बेवसाईट पर डाली गई । बच्चों की शंका समाधान के लिए काउन्सिलिग के कार्य किये गये । इन सभी सकारात्मक प्रयास को ज्यादा मजबूती और पूरी तैयारी के साथ आनेवाले समय में हम लागू करने वाले हैं ।

मद्य निषेध अभियान: बिहार सरकार ने यह महसूस किया कि शराब के कारण मेहनतकश लोक परिश्रम से अर्जित धन एवं स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं । महिलाओं, बहु-बेटी के सम्मान के लिए, बच्चों के

उज्ज्वल भविष्य के लिए और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार 1 अप्रील, 2016 से नई उत्पाद नीति, 2015 के अन्तर्गत मद्य निषेध लागू कर रही हे । 5000 करोड़ के वार्षिक राजस्व से अधिक मूल्यावान है- हमारे नागरिकों का जीवन । इस अभियान को हर पंचायत, हर टोला, हर द्वार और हर आदमी तक पहुँचाने का बीड़ा शिक्षा विभाग ने उठाया है ।

हम सबका ये अभियान है,

नशामुक्ति पैगाम है ।

महात्मा गॉधी अपने चम्पारण आन्दोलन के क्रम में बरहरवा लखनसेन में वर्ष 1917 में पहला विद्यालय स्थापित किया था और नशा से दूर रहने की अपील लोगों से की थी । गॉधी के चम्पारण आन्दोलन के सौवें वर्ष में बिहार ने गॉधी के सपने को लेकर जनअभियान चलाने का संकल्प लिया है । गॉधी ने कहा था शराब से शरीर नष्ट होता है और आत्मा भ्रष्ट होती है । शराब का सेवन करने वाला इन्सान हैवान हो जाता है।, गॉधी के इस संदेश को पूरा करने की हमने कसम खायी है । बच्चों की मदद से हम सभी अभिभावकों से मद्य निषेध का शपथ दिलवा रहे हैं ।

124 कला जत्था की टीम हर गली-मुहल्ले में, चौक-चौराहे पर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश पहुँचा रही है । हमारे दलित-महादलित कार्यकर्त्ता, साक्षर भारत के प्रेरक, तालिमी मरकज के स्वयंसेवक, टोला सेवक और साक्षरता सेनानी घर-घर, द्वार-द्वार मुख्यमंत्री का अपील लेकर सम्पर्क अभियान चला रहे हैं ।

प्राथमिक शिक्षा: प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन, शिक्ष नियोजन, भौतिक संरचना की व्यवस्था करने में हम सफल हुए हैं । अब गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए हमारा अभियान चल रहा है । असर रिपोर्ट, के अनुसार पूरे देश में शिक्षा में गुणवत्ता की स्थिति चिन्ताजनक है परन्तु बिहार ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शिक्षकों की क्षमता में सुधार लाये वगैर सम्भव नहीं है । शिक्षा विभाग ने 5 मार्च को यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के साथ-साथ देश के कुछ प्रमुख शिक्षा संबंधी संस्थान प्रथम अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन, सुपर-30 के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, इसमें शिक्षकों के कार्यस्तर में सुधार के अनेक उपाय पर चर्चा हुई, यह भी तय किया गया कि इन संस्थानों के साथ मिलकर कुछ प्रखण्डों में प्रायौंगिक कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे । इतना ही नहीं सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी सत्र से सरकारी स्कूल में भी प्रत्येक कक्षा के छात्र-छात्राओं का नियमित मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा । हमें याद रखना हो कि आर.टी.ई. के तहत हम किसी बच्चा को कक्षा में उत्तीर्ण होने से रोक नहीं सकते फिर भी सततृ मूल्यांकन से बच्चों का शैक्षणिक स्तर का पता चलता रहेगा । स्कूल में परीक्षायें बंद हो जाने के कारण छात्र पहली बार जब दसवीं की बोर्ड परीक्षा देने लगते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं । इसलिए इस वर्ष 29 एवं 30 मार्च को हम आठवीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट टेस्ट लेने जा रहे हैं ताकि हमे पता रहे कि नौवी एवं दसवीं परीक्षा के लिए किस स्तर के विद्यार्थी उलब्ध होंगे और उनके सुधार के लिए क्या किया जा जा सकता है ।

स्कूल और छात्रों को उत्साह करने के लिए पुरस्कार योजना को भी लागू करने का सरकार विचार कर रही है । इसमें प्रत्येक जिले के 10 सबसे अच्छे विद्यार्थी और प्रत्येक जिला के 10 सबसे अच्छे स्कूल को पुरस्कृत करने का सरकार विचार कर रही है।

वर्ष 2016 से हम वर्ग आठ के स्तर पर वार्षिक परीक्षा लागू कर रहे हैं । इसका उद्देश्य बच्चों में अन्तर्निहित क्षमता का पता लगाना, उनके शैक्षिक संवर्द्धन हेतु उपाचारात्मक शिक्षण(Remedial Teaching) करना एवं पढ़ाई के प्रति उनमें लगन पैदा करना है । इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक में सुधार, बेहत शिक्षण प्रणाली, नियमित निरीक्षण जैसे उपाय हम लागू कर रहे हैं ।

प्राथमिक शिक्षा में उपलब्धि के कारण, बालिका शिक्षा के लिए अनेक प्रोत्साहन योजना चलने के कारण और ग्रामीण स्तर पर नियोजन के अवसर मिलने के कारण माध्यमिक शिक्षा की मांग पूरे बिहार में प्रबल है । यद्यपि भारत सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राशि की अपर्याप्त यवस्था की है । हमारे विरोधी दल के लोग है नहीं, वे बार-बार कहते हैं कि शिक्षा और बिहार के प्रति संवेदनशील है। शिक्षा जैसे विभाग में इनकी असंवेदनशलीता नजर आती है । महोदय, आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहते हैं कि शिक्षा पर भारतीय जनतापार्टी और उनकी नई सरकार बिहार के लिए बड़ी-बड़ी बाते करती है, कुल इस वित्तीय वर्ष में कुल जो बिहार शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा में कुल स्वीकृत बजट था 7387.15 करोड़ रूपया, स्वीकृत केन्द्रांश था 4032.29 करोड़ रूपया मगर इन्होंने विमुक्त किया मात्र 2515.57 करोड़ रूपया, मात्र 57 प्रतिशत पैसा ही इन्होंने विमुक्त किया है और बकाया केन्द्रांश सिर्फ सर्वशिक्षा अभियान में 1916.72 करोड़ रूपया है, अगर भारतीय जनता पाटी के नेता और उनके प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठते

तो उनसे आग्रह करते कि अगर बिहार की इतनी चिन्ता है तो शिक्षा व्यवस्थ को सुदृढ़ करने की इतनी इच्छा है तो कम से कम जायं और प्रधानमंत्री से और शिक्षा मत्री से मिलकर के जो बिहार का हमारा हक है उसको दिलाने का काम करें । आर.एम.एस.ए. में 125.80 करोड़ है, स्वीकृत अनुदान है 98.16 करोड़ है और विमुक्त केन्द्रांश मात्र 36.00 करोड़ रूपया है, मात्र 36.25 प्रतिशत पैसा आर.एम.एस.ए. में विमुक्त करने का काम किया है । बकाया केन्द्रांश 62.15 करोड़ रूपया है ।

माध्यमिक शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(आर. एम.एस.ए.) में केन्द्र द्वारा कुल स्वीकृत बजट 1321 करोड़ रूपया है, विमुक्त 299 करोड़ रूपया है, बकाया केन्द्रांश 1022 करोड़ रूपया के आस-पास है। मॉडल स्कूल में, जो केन्द्र सरकर की योजना थी, 575 करोड़ रूपया बकाया है । और रूसा में, उच्चतर शिक्षा में एम.एस.आर. डी. से स्वीकृत राशि 264 करोड़ रूपया है, लेकिन विमुक्त राशि 2.2 करोड़ रूपया है, लम्बित राशि 57.2 करोड़ रूपया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश में राजनीत तो करते हैं, बोलते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन जितना धरना प्रदर्शन विधान सभा और विधान सभा के बाहर करते हैं लेकिन ये जाकर के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के पास बैठकर बिहार के शिक्षा का पैसा अगर रिलिज कराते तो बिहार के बच्चों का कल्याण होता ।

इसके वाबजूद भी आगामी वर्ष में हमारे जो 2939 विद्यालय हैं, उसको अपग्रेड करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धि के बाद, कर्णांकित अपर्याप्त राशि के बावजूद भौतिक संरचना में नगण्य प्रावधान किया गया है, बावजूद इसके बिहार सरकार अपने संसाधन से उच्च विद्यालय के भौतिक संरचना को बढ़ाने का काम कर रही है, इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि उल्लेखनीय है, 726 उत्क्रमित

उच्च विद्यालय, 993 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 343 मॉडल स्कूल एवं 194 बालिका छात्रावास के भवन के निर्माण का कार्य हमने शुरू किया था । जिसमें 433 उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन, 365 उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन, 216 मॉडल स्कूल एवं 84 बालिका छात्रावास के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, शेष निर्माणाधीन है ।

माध्यमिक शिक्षा में पूरे बिहार में हर पचायत में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था हेतु सरकार ने अभियान चलाया है । वर्तमान में 2,158 पंचायतों में मध्य विद्यालय को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया । शेष 2,939 को आगामी वर्ष में करने की हमारी प्रतिबद्धता है ।

बालिकाओं के लिए साईकिकल योजना चलायी गयी । क्रमशः

टर्न-21-09:03-2016-ज्योति

श्री अशोक चौधरी : ...क्रमशः..ये योजनाएं न केवल माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अभियान चलाए गए , ऐसी योजनाएं शुरू की गयीं जिससे नारी सशक्तीकरण और हमारी बालिकाएं हैं जो पढ़ती नहीं थी , जो स्कूल जाती नहीं थी , उसमें एक लम्बा छलांग लगाने का काम बिहार सरकार ने किया है । उनको सशक्त बनाने की योजना है छात्रवृति , किताबें , प्रोत्साहन की योजनायें चलायी गयीं हैं । परिणामतः 2016 की मैट्रिक की परीक्षा में 7 लाख। 20 हजार 277 बालिकाएं शामिल हुई हैं । 46 प्रतिशत पूरा राज्य में जो हमारा पार्टिसिपेशन है उसका 46 प्रतिशत खाली बालिकाएं हैं । लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि विगत दो वर्ष में मैट्रिक और इन्टर की परीक्षा में बालिकाओं द्वारा प्रदर्शित हुई है । यहं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का वीजन है , मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि एक ऐसा लीडर हमको मिला है जिसके पास वीजन है , जो आने वाले दस साल की राजनीति करने पर आमादा है ।

लड़कियों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा के साथ साथ उन्हें जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी दी जा रही है । किशोरी बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन हेतु नगद राशि का भुगतान इस वर्ष से किया जा रहा है । शिक्षक नियोजन पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगामी महीनों में हम माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में शिक्षकों को नियोजित करने हेतु विशेष उपाय करेंगे । निश्चित रुप से आज ये बात नियोजन करने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को है उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं उसमें हम कैसे त्रुटियों को दूर करें , कैसे उसको व्यवस्थित करें जिससे हमारा नियोजन की जो प्रक्रिया है वह और सरल हो सके । इसपर भी हम विचार कर रहे हैं । बहुत से सदस्यों ने इस बात पर प्रश्न उठाया था तो सरकार इन बातों को देख रही है ताकि हम उसको सरल बना सके ।

नेतरहाट की तर्ज पर हमारा सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय चल रहा है । पहली बार वर्ष 2015 में इस विद्यालय के बच्चे बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए । बिहार

बोर्ड के प्रथम 10 स्थानों में 09 स्थानों पर इस विद्यालय से 31 छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं । हमको एक सूचना देनी है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में जो हमारा सैनिक स्कूल खुलवाने का काम किया , पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छा परफौरमेंस इस विद्यालय का है, मुझे यह सदन को सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि 15-16 के शैक्षणिक सत्र में सैनिक स्कूल, नालन्दा के 21 कैडेट एन0डी0ए0 में प्रवेश पाने में सफल हुए हैं । 9 और कैडेटों का चुनाव हो चुका है । जुलाई 2016 में दाखिला प्राप्त करेंगे । निश्चित रुप से हमारा सैनिक स्कूल राजगीर जो है वो एक अच्छा काम कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार गठन के ठीक बाद ही उच्च शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । 11 जरवरी को रुसा की बैठक और फिर 18 जनवरी को महामहिम राज्यपाल के साथ सभी वाईस चांसलरों की बैठक बुलायी गयी जिसमें यू0जी0सी0 के वाईस चेयरमैन भी सम्मिलित हुए थे । राज्य के सभी विद्यालयों और कम से कम सौ कॉलेंजों कों नैक द्वारा मूल्यांकण कराने की दिशा में सघन प्रयास किया जा रहा है। नैक द्वारा मूल्यांकण कराये बिना केन्द्र सरकार से वित्तीय अनुदान अब प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इसे पूर्ण कराने की कोशिश कर रहे हैं । इसी कड़ी में सी0डी0सी0एस0 यानी च्वायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने के विषय में विचार विमर्श किया जा रहा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छात्र अपनी रुचि के हिसाब से मन चाहा विषयों के योग से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं जिससे बी0एस0सी0 करने वाला छात्र यदि चाहे तो अपनी मर्जी से इतिहास या जीव विज्ञान या संगीत कोई विषय का पेपर एक साथ ले सकता है, इन विषयों के बीच की दिवार गिर जाती है और नये विचारों को उत्पन्न करने में हमारी मदद मिलती है । अध्यक्ष महोदय, ग्रौस इनवौल्भमेंट रेशियो में बढ़ोत्तरी में सरकार सजग है ।

बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रखण्ड स्तर पर हमारा डिग्री स्कूल, डिग्री कॉलेज नहीं है उसको व्यवस्थित करने का हमें उपाय करना

चाहिए । वर्तमान में उच्च शिक्षा में राज्य का जी0ई0आर0 13 प्रतिशत है जबकि देश का 23.6 प्रतिशत है । इसे बढ़ाने के लिए तुरत शिक्षा माध्यम से राज्य के 240 प्रखण्डों में उच्च शिक्षा केन्द्र की स्थापना राज्य के महाविद्यालयों , विश्वविद्यालयों में पूर्व निर्धारित नामांकन के सीटों की वृद्धि एवं राज्य के 18 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है । नेशनल असेसमेंट ऐण्ड एक्रीडियेशन नैक राज्य में उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकण कराना अनिवार्य हो गया है। इस कार्य में तीव्रता आयी है और अबतक 49 शिक्षण संस्थनों का मूल्यांकन कराया जा चुका है । वर्ष 2016 तक सभी विश्वविद्यालयों एवं 100 महाविद्यालयों के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, निश्चित रुप से हायर एजुकेशन में महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है । महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा करीब 3500 रिक्तियों के विरुद्ध सहायक प्राध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । विभिन्न विषयों के लिए साक्षात्कार शुरु हो चुका है । सम्प्रति मैथिली एवं अंग्रेजी विषयों की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है तद्नुसार नियुक्ति हो रही है । अध्यक्ष महोदय, निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी राज्य सरकार पूरी तरह से सतत सजग है । राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु कुल 12 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए थे जिसमें 05 संस्थाओं को विश्वविद्यालय खोलने के निमित्त लेटर औफ इन्टेन्ट निर्गत किया गया है । हम चाहते हैं कि बिहार में और भी प्राईवेट यूनिविर्सिटीज आयें और उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमलोग कृतसंकल्प हैं और इसी के लिए हमलोगों ने जो बड़े बड़े इन्सटीच्युट बिहार के बाहर भी हैं , एक हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे तो उनको भी लाने पर विचार कर रहे हैं ।

राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं में एन0सी0टी0ई0 मानक के अनुरुप व्याख्याताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल वांछित अहर्ताधारी शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है । प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता के 1060 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा का

आयोजन प्रक्रियाधीन है । राज्य के सभी राजकीय 66 प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु उनके भवन निर्माण की कार्रवाई बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से कराई जा रही है ।

राज्य के 05 जिलों में जहानाबाद, अरवल, सुपौल , जमुई एवं सहरसा में नये डायट (डिस्ट्रीक्ट इंस्टीच्युट औफ एजूकेशन ऐण्ड ट्रेनिंग) की स्थापना एवं 08 अतिरिक्त नये अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सिवान, पं0 चम्पारण, अररिया, मुंगेर, पटना, बक्सर , औरंगाबाद एवं पूर्णिया की स्थापना प्रक्रियाधीन है ।

विश्व बैंक संपोषित - बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने कहा और हम ये जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे प्रदेश में बहाल हो , ये हमारे मुख्यमंत्री की सोच है इसलिए हमलोगों ने टीचर ट्रेनिंग के लिए विश्व बेंक सम्पोषित ''इनहान्सिंग टीचर इफेक्टीवनेस इन बिहार प्रोग्राम '' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 40 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं 250 प्रशिक्षण केन्द्रों पर आई0सी0टी0 की व्यवस्था की जा रही है ।

शिक्षकों का नया वेतनमान : राज्य में नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 जुलाई, 2015 से नियत वेतन के स्थान पर नये वेतनमान में वेतन का निर्धारण कर वेतनादि भुगतान की कार्रवाई की गयी है । इसके कारण जून, 2015 को दिये जा रहे नियत वेतन में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के तहत 7387.15 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसके तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः 4432.29 करोड रुपया़ एवं 2954.86 करोड़ रुपया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश मद में अबतक प्राप्त राशि 2515.57 करोड़ रुपया है । केन्द्रांश राज्यांश का अनुपात 65:35 के स्थान पर 60:40 कर दिया गया एवं केन्द्रांश मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं करायी गई है

फलत: शिक्षकों के नये वेतनमान में वेतनादि के ससमय भुगतान में कठिनाई का हम सामना कर रहे हैं ।

अबतक कुल स्वीकृत 16330 नये प्राथमिक विद्यालय भवन के विरुद्ध 11416 भवनों का निर्माण। पूर्ण हो चुका है ।

बिहार में वर्ग 1 से 8 तक सभी विद्यालय आने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दोपहर का गर्मागर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है । वर्तमान में नामांकित 62 प्रतिशत बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं । मध्याह्न भोजन योजना का आई0भी0आर0एस0 सिस्टम से अनुश्रवण किया जा रहा है । अनुश्रवण से प्राप्त सूचनाओं को निदेशालय स्तर पर पदाधिकारियों के बीच जिला आवंटित कर समीक्षा की जाती है तथा समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है । आई0भी0आर0एस0 इतना महत्वपूर्ण सिस्टम है कि इसको भारत सरकार भी इस सिस्टम को एडौप्ट करने पर विचार कर रही है ।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के लिए थाली-गिलास उपलब्ध कराया जा रहा है ।

महादलित, दलित, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के बीच कार्य करने वाले टोला सेवकों एवं तालिमी मरकज के स्वयंसेवकों का मानदेय 5000 रुपया से बढ़ाकर 8000 रुपया किया गया । कार्यावधि में मृत्यु होने पर एक मुश्त चार लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान भी लागू किया गया हे ।

विभाग के द्वारा प्रशासन में स्वच्छता लाने एवं नियम विरुद्ध कार्य करने वाले पदाधिकारियों को दंडित करने की कार्रवाई त्वरित गति से की जा रही है। अबतक घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए मामले, अनुपातिक रुप से अधिक धन उपार्जन करने वाले मामले एवं पद के दुरुपयोग संबंधी मामलों में 37 कर्मियों की सेवा

समाप्त की गयी है । 8 कर्मियों का शत-प्रतिशत पेंशन जप्त किया गया है एवं 17 कर्मियों के विरुद्ध अन्य दंड अधिरोपित किए गए हैं ।

संक्षेप में मैंने आपके समक्ष शिक्षा विभाग में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी है । विस्तृत सूचना हमारे वार्षिक प्रतिवेदन में रखा गया है । हम आपसे आग्रह करते हैं कि शिक्षा का कार्य बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का कार्य है, शिक्षा का कार्य युवाओं के जीवन में आशा का संचार का कार्य है, शिक्षा का कार्य गरीब, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य है, शिक्षा का कार्य अन्धकार के विरुद्ध प्रकाश फैलाने का कार्य है । आइये इस कार्य में हमलोग साथ मिलकर, राजनीति से ऊपर उठकर राज्य हित में, जनहित में कार्य करने का संकल्प लें । मैं नेल्शन मंडेला के कथन को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ ।

'' शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है । आइए हम सब मिलकर दुनिया को सुंदर, सुखमय, शान्तिमय बनाने के लिए काम करें । ''

क्रमशः

टर्न-22/विजय/ 09.03.16

श्री अशोक चौधरीः क्रमशः हम एक बात और सदन को बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और विभाग नहीं महाविभाग है । हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे उपर विश्वास किया और शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया है । हम आपको पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने के लिए हम कटिबद्ध हैं । मात्र चार महीना हमें हुआ है हमलोगों की सरकार को मात्र चार महीना हुआ है और सरकार में हम आए हैं । विभाग को समझने में विभाग को देखने में ही चार महीना चला जाता है । लेकिन हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं यह सरकार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लायेगी । हम चाहते हैं कि जिसके बलबूते पर यह महागठबंधन की सरकार बनी है गरीब, दलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा जिनके बदौलत हमारी सरकार बनी है प्राथमिक जो विद्यालय हमारे हैं जो टोला हैं उन प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं जिनके बलबूते पर हम इस सदन में आये हैं और अपनी बात को हम रख रहे हैं निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा में गुणवत्ता को लाने का प्रयास करेंगे । और निश्चित रूप से हमारे शिक्षको की जो व्यवस्था है एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि हम अशिक्षा के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिर्फ सरकार के बदौलत नहीं लड़ी जा सकती है । इसलिए समाज और इस सदन के राजनीतिक दल के लोग समाज के जो सामाजिक लोग हैं सबको साथ आना होगा । अशिक्षा के खिलाफ बड़ी लड़ाई को आधार बनाना होगा । जिस भूख की हम बात करते हैं जो बड़े सम्पन्न परिवार हैं उनमें तो शिक्षा के लिए भूख है लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो दो वक्त की रोटी खाते हैं उनमें शिक्षा की भूख नहीं है । इसलिए उनके भूख को जगाना है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इस सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस प्राथमिक विद्यालय को सुदृढ़ करने का काम करेंगे और नीतीश कुमार की जो नीति है हम गुणवत्ता की शिक्षा इस बिहार में लागू करेंगें, पूर्ण तरह से हम लागू करेंगे ।

इसलिए हम सदन से आग्रह करते हैं कि हमारे मांग को मान लिया जाय, स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज शिक्षा विभाग के मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है इसलिए मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है,

कि शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च,2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 218,97,02,24,000/- (दो सौ अठारह अरब संतानवे करोड़ दो लाख चौबीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: आज दिनांक 9 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 21 (इक्कीस) है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

शोक-प्रकाश

स्वर्गीय रामवरूप प्रसाद

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा एवं लोक सभा के पूर्व सदस्य श्री रामस्वरूप प्रसाद का निधन दिनांक 08.03.2016 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय प्रसाद नालंदा जिला के एकंगरसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 एवं इस्लामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985, 2000, मार्च, 2005 एवं नवम्बर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे 1989 एवं 2006 में नालंदा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे । उन्होंने नालन्दा जिलान्तर्गत कई शैक्षणिक सस्थाओं का निर्माण किया था । वे हमेशा गरीबों एवं जरूरतमन्दों की सेवा में तत्पर रहा करते थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

अब हमलोग एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्ष: मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक, वृहस्पतिवार दिनांक 10 मार्च, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....